



# युवा कांग्रेस के चुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप, खुद कैडिडेट वीडियो बनाकर लगा रहे आरोप

**राजनांदगांव।** छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर फर्जी वोटिंग किए जाने का आरोप खुद कैडिडेट ही खुलकर कर रहे हैं। जिला शहर अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे अमर झा और विप्लव शर्मा सहित अन्य कैडिडेट ने सोशल मिडिया में अपनी बात रखी हैं और वीडियो बनाकर इसे शेयर किया है। उम्मीदवार अमर झा ने वीडियो जारी कर कहा है कि मेरे मोबाइल को आईडी हैक हो गई है। हमारे नंबर से विरोधी के पक्ष में वोटिंग हो रही



है। जिसकी उन्होंने आरओ से शिकायत की है। वहीं उम्मीदवार विप्लश शर्मा ने कहा है कि

उनके मोबाइल की आईडी हैक कर उनके ही मोबाइल से दूसरे पक्ष को वोटिंग हो रही है। उनके नंबर पर दूसरे का आईडी दिखा रहा है, जिसको आरओ से शिकायत हुई हैं।

बता दे पिछले एक माह से युवा कांग्रेस का चुनाव प्रदेश में जारी है। जिसमें सदस्यता अभियान के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। सदस्यता अभियान का 29 सितंबर को अंतिम तिथि होना बताया जा रहा है।

शहर जिलाध्यक्ष पद के लिए राजनांदगांव

शहर से शहर जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के जितेन्द्र मुदलियार के खेमे से मैदान पर अमर झा है। वहीं लिखिल द्वेदी के खेमे से विप्लव शर्मा और आसिफ अली व संतोष पिब्ले के खेमे से मैदान में अनिस खान मैदान में है। तीनों की कैडिडेट का मजबूत माना जा रहा था, और लगभग तीनों के बीच जंग चल रही थी। लेकिन अंतिम दिन सोशल मीडिया में फर्जी वोटिंग का वीडियो वाइरल होने के बाद राज्य से लेकर केन्द्र स्तर पर बवाल मच गया

है। खुद कैडिडेट द्वारा इस तरह का आरोप लगाए जाने से उच्च स्तर के नेताओं में भी नाराजगी सामने आ रही है। हालांकि, अमर झा और विप्लव शर्मा द्वारा जारी किए गए वीडियो में उन्होंने कहा है कि उन्होंने फर्जी वोटिंग की शिकायत आरओ से की है। इस मामले में राजनांदगांव जिले के रिटर्निंग अधिकारी सतीश आर्यन का कहना है कि शिकायत आई है, कितनी आई देखकर बता पाएंगे। उन्होंने कहा हैक जैसी कोई समस्या नहीं है, एए सही

चल रहा है।

राजनांदगांव जिले में शहर जिलाध्यक्ष के लिए सामने आए उम्मीदवारों ने करीब 15 हजार रिकार्ड सदस्य बनाया है। सदस्यता बनाने की फीस 75 रूपए निर्धारित थी। सदस्यता बनाए जाने के बाद तत्काल ऑनलाइन वोटिंग किया जा रहा था। युवा कांग्रेस चुनाव में शहर अध्यक्ष व ग्रामीण अध्यक्ष के आलावा महासचिव के लिए चुनाव चल रहा था।

## नवनियुक्त हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने सुनी बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार से जुड़ी याचिका

**बिलासपुर।** बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार से जुड़ी दो जनहित याचिकाओं की नए चीफ जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा और जस्टिस संतोष शर्मा की खंडपीठ में पहली बार सुनवाई हुई। प्रकरण को समझने के बाद चीफ जस्टिस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिवक्ता से गत निर्देश के अनुरूप स्पष्टता के साथ नया शपथ पत्र देने को कहा. मामले की सुनवाई अगली अब 13 अक्टूबर को रखी है।

सुनवाई के प्रारंभ में याचिकाकर्ताओं की ओर से विरुद्ध अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव और अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बिलासपुर में एयरपोर्ट के आवश्यकता छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर के महत्व और पिछले लगातार कई सालों से हाई कोर्ट के द्वारा इसी जनहित याचिका की सुनवाई की की जा रही मॉनिटरिंग के बारे में खंडपीठ को अवगत कराया।

गौरतलब है कि जहां



### एएआई को दिए स्पष्ट निर्देश

चीफ जस्टिस कृष्णा राम मोहपात्रा हाल ही में छत्तीसगढ़ चीफ जस्टिस बने हैं वहीं जस्टिस संतोष शर्मा ने भी अभी ही जस्टिस का पदभार ग्रहण किया है। इस हिसाब से उन्हें प्रकरण के पूर्व के घटनाक्रम और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों के बारे में उन्हें विस्तार से अवगत कराया गया।

प्रकरण को समझने के बाद चीफ जस्टिस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिवक्ता से सवाल किया कि गत निर्देश के अनुरूप क्या आपके द्वारा नया शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है, और

उन्होंने यह भी कहा की शपथ पत्र स्पष्ट होना चाहिए तथा ऐसे अधिकारी का होना चाहिए, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो।

गौरतलब है कि AAI पिछले काफी समय से राज्य सरकार के द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट का ऑपरेशन प्रबंधन और विकास का कार्य लेने के प्रस्ताव पर स्पष्ट मत नहीं दे रही है। राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने भी कहा कि पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देश के अनुसार वे भी एक शपथ पत्र दाखिल कर रहे हैं।

## तीन महीने में उखड़ी 43 लाख की सड़क, फिर से बनाने के दिए निर्देश

**कवर्धा।** सड़क निर्माण में लापरवाही बरतना ठेकेदार को भारी पड़ गया। गांव के विकास के लिए बनी 43 लाख रुपए की सड़क महज तीन महीने में उखड़ने लगी तो विभाग ने खराब सड़क पर बुलडोजर चलाया और ठेकेदार को फिर से बनाने के निर्देश दिए। पूरा मामला पंडरिया ब्लॉक के गुंटेठा गांव का है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं ग्रामीण विकास योजना के तहत करीब 550 मीटर सीसी रोड का निर्माण कराया गया था। सड़क बनने के कुछ ही महीनों बाद इसकी गिटी उखड़कर बाहर आने लगी और गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। अधिकारियों ने सड़क निर्माण को लेकर ठेकेदार को साफ निर्देश दिए थे कि सड़क इंजीनियर की उपस्थिति में बनाएं,



लेकिन ठेकेदार ने मनमानी करते हुए अधिकारियों की बातों को अनसुना कर जबरदस्ती सड़क बनवा दिया। सड़क तीन महीने में ही उखड़ने लगी। इसकी शिकायत मिलने पर अधिकारी ने एक्शन मोड में आते हुए खराब सड़क पर बुलडोजर चलवा दिया।

ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और गुणवत्ता की अनदेखी का आरोप लगाते हुए संबंधित विभाग से शिकायत

की थी। शिकायत के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सड़क की जांच कराई। कोर कटिंग के जरिए सड़क के सैंपल लिए गए और तकनीकी जांच के लिए लैब भेजे गए। जांच में सड़क गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरी। इसके बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए खराब सड़क पर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ने की कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां-जहां सड़क खराब मिली है, वहां सड़क को तुड़वाकर दोबारा गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाई जाए। बताया जा रहा है कि विभाग ने ठेकेदार के भुगतान पर भी रोक लगाई है। वहीं, ठेकेदार की ओर से लिखित रूप से गलती स्वीकार करते हुए सड़क को दोबारा बनाने का भरोसा दिया गया है।

## कबीरधाम की सुरक्षा व्यवस्था में ब्लाइंड स्पॉट

**कबीरधाम।** शहर की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चौक-चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे कई जगहों पर बंद पड़े हैं। लाखों रुपये की लागत से लगाए गए इन कैमरों का मकसद शहर की गतिविधियों पर नजर रखना और किसी भी आपराधिक घटना के बाद पुलिस को जांच में मदद पहुंचाना था। लेकिन कैमरों के बंद होने से सार्वजनिक निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।

किसी भी वारदात के बाद सीसीटीवीफुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग साबित होता है। आरोपी किस रास्ते से घटनास्थल तक पहुंचा, वारदात के बाद किस



दिशा में गया और रास्ते में उसकी गतिविधियां क्या रहीं, इन सभी सवालों के जवाब सीसीटीवी के जरिए पुलिस तलाशती है। ऐसे में शहर के प्रमुख स्थानों पर लगे सरकारी कैमरों का बंद होना पुलिस की जांच

को प्रभावित कर सकता है।

वर्तमान समय में सीसीटीवी अपराध नियंत्रण, सड़िधर्म की पहचान और घटनाओं की जांच में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लगे सरकारी कैमरों का लंबे समय तक बंद रहना सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से गंभीर विषय माना जा रहा है।

अब जनता के सामने बड़ा सवाल ये है कि कैमरों को अपडेट करने का काम कितनी जल्दी पूरा होता है।क्योंकि यदि इस बीच कहीं बड़ी वारदात हुई और निजी कैमरों में वारदात से जुड़ी गतिविधियां कैद नहीं हुईं तो पुलिस को अपराध को सुलझाने में काफी मशक़त करनी पड़ेगी।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

### 4 अक्टूबर से ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा अग्रसेन जयंती महोत्सव

**राजनांदगांव।** अग्रवाल समाज के अधिष्ठाता देव भगवान अग्रसेन की जयंती को लेकर अग्रवाल सभा ने भव्य अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2026 को ध्वजारोहण के साथ होगा और विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों का सिलसिला 11 अक्टूबर को मुख्य समारोह तक चलेगा। महोत्सव में बच्चों, युवाओं, महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष सुशील अग्रवाल, नवयुवक मंडल अध्यक्ष चैतन्य अग्रवाल एवं महिला मंडल अध्यक्ष संतोष राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अग्रसेन भवन में जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अग्रसेन भवन की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्य अतिथि नरेंद्र गोयल ध्वजारोहण कर महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। अग्रवाल सभा के सचिव अशोक लोहिया ने बताया कि महोत्सव के पहले दिन ही विभिन्न आयोजन होंगे।

## पकड़ा गया बबन का हत्यारा शहडोल में बनाया था ठिकाना

**कोरबा।** पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी उस वक्त पकड़ा गया जब वो अपने परिवार से मिलने घर पहुंचा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में छिपा हुआ था। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पसान थाना पुलिस ने बताया कि वारदात वानांचल इलाके के पसान थाना क्षेत्र के ग्राम पपरिया, सिपतपारा का है। यहां पर 85 साल के बबन राम यादव की की पुश्तैनी जमीन है। इस जमीन का बबन के दूसरे भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारे को लेकर बबन यादव के छोटे भाई के बेटे, अशोक कुमार यादव, उम्र 23 साल, से विवाद चल रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच बहस होने लगी। आरोप है कि बबन राम यादव ने लाठी से भतीजे अशोक कुमार यादव पर हमला बोल दिया। इस बात से नाराज भतीजे ने पास रखे कुल्हाड़ी से अपने चाचा पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। जानलेवा हमले में बबन राम यादव की मौत हो गई।

## सीआरपीएफ जवान सालिक धुव का धमतरी में अंतिम संस्कार

**धमतरी।** सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) में तैनात परेवाडीह के रहने वाले जवान सालिक ध्रुव का निधन बिहार में हो गया। मंगलवार को जवान सालिक ध्रुव का पार्थिव शरीर रायपुर से उनके पैतृक घर पर लाया गया। पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जवान के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आस पास के लोग पहुंचे। अंतिम संस्कार से पहले सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने उनको नमन किया और उनको अंतिम विदाई दी। परिवार वालों के मुताबाकि, ग्राम परेवाडीह निवासी सालिक ध्रुव, पिता घासीराम ध्रुव 32 साल के थे। जवान सालिक ध्रुव ने साल 2016 में सीआरपीएफ में भर्ती होकर देश की सेवा शुरू की थी। निधन से पहले वो बिहार के गया में पदस्थ थे। कुछ दिनों पहले अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनका इलाज रायपुर में चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जवान के निधन की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे परेवाडीह में शोक की लहर दौड़ गई।

## दुर्गा प्रतिमाओं पर महंगाई का पड़ा असर, मूर्तिकारों की बढ़ी समस्या

**बलरामपुर।** 11 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। रामानुजगंज में बंगाल से आए मूर्तिकार तेजी से दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रुप देने में जुटे हैं। मूर्तिकार चाहते हैं कि 10 तारीख से पहले-पहले पूजा पंडालों तक मूर्तियां पहुंच जाएं। बंगाल से मूर्तियां बनाए आए कलाकार कहते हैं कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसका असर उनके कारोबार पर भी पड़ा है। कच्चे माल की कीमतों में कई गुणा इजाफा होने से उनको समान महंगे दरों पर खरीदना पड़ रहा है। इसकी वजह से मूर्तियों के दाम बढ़ाना उनकी मजबूरी है। मूर्तिकार कहते हैं कि दादा परदादा के समय से उनके यहां यही काम होता आया है, लिहाजा पुश्तैनी काम होने के चलते वो इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। बंगाल से आए मूर्तिकार रंजीत मंडल ने कहा, वो पिछले 22 सालों से लगातार मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। हर साल सामान का दाम बढ़ता जा रहा है। वो यहां पर सबसे पहले गणपति की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। गणपति पूजा के बाद दुर्गा पूजा के लिए प्रतिमाओं का निर्माण कार्य शुरू करते हैं।

## निःशुल्क उपचार से 12 वर्षीय तरुणा को मिला स्वस्थ जीवन

**महासमुंद।** पीएम की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा सेवा, समर्पण और जनकल्याण के संकल्प की प्रेरणादायी यात्रा रही है। इसी सेवा भावना को जन-जन तक पहुंचाने और जरूरतमंदों के समय पर शासकीय योजनाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम महासमुंद जिले में भी देखने को मिल रहा है। विकासखंड बागबाहरा की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाळा धानपुर की कक्षा 7वीं में अध्ययनरत 12 वर्षीय कुमारी तरुणा यादव की कहानी इसी जनसेवा की एक मिसाल है। बचपन से जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित तरुणा को खेलने-कूदने, दौड़ने और सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती थी। परिवार इसे सामान्य कमजोरी समझता रहा। विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंचे चिरायु दल ने तरुणा की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को गंभीरता से लिया। जांच एवं चिकित्सकीय परामर्श के माध्यम से उसके जन्मजात हृदय रोग की पहचान की गई। समय पर हुई।

## दुर्ग जप में सत्ता पक्ष ने अपने सदस्यों के बीच 16वें वित्त की राशि के आवंटन का लिया फैसला

**दुर्ग।** दुर्ग जनपद पंचायत की सामान्य सभा में सत्ता पक्ष ने 16वें वित्त की राशि अपने सदस्यों के बीच उनके क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है। विपक्षी सदस्यों ने क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक सदस्य के क्षेत्र में देने की मांग रखी। मांग नहीं माने जाने पर 16वें वित्त की राशि से वंचित विपक्षी सदस्यों ने नाराजगी जताते जमकर नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया।

जानकारी के अनुसार, बैठक में विभागीय समीक्षा उपरांत 16वें वित्त पर चर्चा शुरू हुई इसमें जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन ने बहुमत के आधार पर इसकी राशि आवंटन की बात रखी। उपाध्यक्ष राकेश हिरवानी ने इस पर आपत्ति करते हुए जसंख्या के आधार पर प्रत्येक सदस्य को आवंटित करने की मांग की। मगर अध्यक्ष बहुमत के



आधार पर आवंटन को लेकर अड़े रहे, तब हिरवानी ने कहा कि पांच दिन पहले आपसी विवाद खतम कर समन्वय बनाकर सभी सदस्यों के क्षेत्र के लिए बराबर आवंटन करने की सदस्य भी मतदान चाहते हैं। इस पर अब अचानक टालमटोल क्यों किया जा रहा है। हिरवानी ने आरोप लगाया कि दुर्ग ग्रामीण विधायक के मना करने पर आप यह कर रही हो, यदि विधायक

जनपद में इस तरह हस्ताक्षेप करेंगे तो उनके सदन में बैठने का वे विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुमत के आधार पर आवंटन करना है, तो मतदान कराओ क्योंकि बहुत सारे सत्ता पक्ष के सदस्य भी मतदान चाहते हैं।

अध्यक्ष ने मतदान न कर खुले रूप में बहुमत साबित करने की बात कही और गुप्त मतदान न करा कर हाथ उठवा कर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर बैठक

स्थगित करने की घोषणा कर दी।

गुप्त मतदान से बहुमत पारित नहीं कराए जाने पर नाराज विपक्षी सदस्यों राकेश हिरवानी, झूमित गायकवाड़, संतोषी देशमुख, ढालेश साहू, राजेन्द्र ठाकुर, कामिनी साहू, किशोरी देशमुख, लीलावती देशमुख, प्यारी निपाद, मिलंतीन ठाकुर ने रोष जताया आक्रोशित विपक्षी सदस्यों ने विधायक ललित चंद्राकर एवं अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, और मनमानी किए जाने का आरोप लगाया।

जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन का कहना है कि सदस्यों की सहमति अनुसार बहुमत के आधार पर 16वें वित्त की राशि आवंटन का निर्णय लिया है जब हाथ उठाकर बहुमत साबित हो गया तो इसके लिए मतदान की क्या जरूरत है।

## कचना धुर्वा पैरी नदी ग्राम सभा फेडरेशन ने उठाई जल-जंगल-जमीन की आवाज

**गरियाबंद।** कचना धुर्वा पैरी नदी ग्राम सभा फेडरेशन, बिंदानवागाढ़ के नेतृत्व में बुधवार को क्षेत्र के 30 पंचायतों की ग्राम सभाओं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हजारों ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट से करीब तीन किलोमीटर पहले से विशाल रैली निकालते हुए नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के समक्ष अपनी आवाज बुलंद की।

कलेक्ट्रेट पहुंचने पर पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में बेरीकेडिंग एवं सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद ग्रामीण शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर उठे। प्रदर्शन के दौरान विस्थापन के विरोध, ऋक्षरुद्धरुद्धक प्रभावी क्रियान्वयन, हाथी प्रभावित गांवों की सुरक्षा एवं किसानों को उचित मुआवजा तथा ग्राम सभा के अधिकारों



को प्रमुखता से उठाया गया।फेडरेशन की ओर से राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं जिला कलेक्टर के नाम तीन अलग-अलग ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपे गए। खास बात यह रही कि कलेक्टर स्वयं हजारों ग्रामीणों के बीच पहुंचकर जापन लेने आए और प्रतिनिधिमंडल से विस्तारपूर्वक चर्चा की। कलेक्टर ने जिला स्तर की मांगों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने तथा शासन स्तर की मांगों को शासन को पत्र भेजकर अवगत कराने की बात कही। जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ऋक्ष और रुरुक्ष की

भावना का वास्तविक पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा, ऋग्राम सभा को केवल बैठक और कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं किया जा सकता। वन अधिकार अधिनियम ग्राम सभा और वन अधिकार धारकों को जंगल, जैव विविधता एवं सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। उन्होंने कहा कि विस्थापन हो या जंगल से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय, ग्रामीणों को केवल सूचना देने के बजाय कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा की भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा, ऋ्राम विकास और संरक्षण दोनों के पक्ष में हैं, लेकिन संविधान और कानून की कीमत पर नहीं। ऋक्ष और रुरुक्षहमारे अधिकार हैं और इनका पूर्ण पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

## संक्षिप्त समाचार

## देहदान करने वाले दानदाता को मृत्युपरान्त मिले राजकीय सम्मान : उपासने



रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जापन देकर निवेदन किया की किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल में मृत्यु पश्चात अपना शरीर परमार्थ हेतु दान देने की घोषणा व आवश्यक कार्यवाही करना दानदाता व उनके परिवार के विशाल हृदय की महानता ब मिसाल होती है। उपासने ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया की ऐसे देह दानदाता का मृत्यु उपरांत राजकीय सम्मान के साथ देह दान की कार्यवाही सम्पन्न की जावे। आज मेडिकल क्षेत्र में ऐसे अंगदान की महती आवश्यकता अध्ययन हेतु होती है। जिसके आधार पर अध्ययन कर कुशल डॉक्टर पढ़ कर निकलते हैं। यह कार्यवाही संदेश देने वाली जनहित कार्यवाही होगी।उपासने ने बताया की मुख्यमंत्री से सुझाव की प्रशंसा करते हुए योग्य कार्यवाही शासन स्तर पर की जाएगी।

## पशुधन विकास विभाग में 17 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ बने 3५ संचालक

रायपुर। पशुधन विकास विभाग ने 17 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) को उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें (राजपत्रित, प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नत किया है। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। पशुधन विकास विभाग ने यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 6 जुलाई को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में गई अनुशंसा के अनुपालन में 17 पशु चिकित्सा सहायक यज्ञों (वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 ) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उप संचालक के पद पर वेतनमान 67300-213100 रुपए (वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) में 23 जुलाई को जारी विभागीय समसंख्यक आदेश द्वारा पदोन्नत किया गया था।

## मंत्रालय की स्टाफ बस नीर भवन के पास फेल, कोई हताहत नहीं

रायपुर। पुराने शहर से मंत्रालय के कर्मचारियों को लेकर जा रही रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट की बस क्रमांक सीजी 04 ई 2817 का ब्रेक नीर भवन के पास चालक के नियंत्रण खो बैठने के कारण फेल हो गया और बस पड़ से जा टकराई लेकिन इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना ने एक बार फिर स्टाफ बसों के फिटनेस और सुरक्षित सफर को लेकर सवाल खड़े कर दिया है। उल्लेखनीय है कि बीते गुरुवार शाम को ही लो फ्लोर स्टाफ बस धू धू कर खाक हो गई थी। उसके बाद परिवहन विभाग ने मंत्रालय की सभी 100 बसों का फिटनेस टेस्ट किया था। इसमें 70 से अधिक बसें कंडम पाई गई थी। इस चेकिंग में यह भी बस भी थी। उसमें इसे फिट बताया गया था। आज की घटना ने परिवहन विभाग के चेकिंग अभियान की भी पील खोल दी है।

## रेलवे आरक्षण केंद्र के पास स्थित दोपहिया पार्किंग एक्सप्रेसवे के पास स्थानांतरित

रायपुर। रायपुर रेलवे स्टेशन के शहर साइड में चल रहे स्टेशन पुनर्विकास एवं निर्माण कार्यों के महेनजर यात्रियों की सुविधा और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए आरक्षण केंद्र के पास स्थित दोपहिया वाहन पार्किंग स्थल को एक्सप्रेसवे के पास स्थानांतरित किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर स्टेशन के शहर साइड में एक्सप्रेसवे के पास दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आरक्षण केंद्र के समीप वर्तमान दोपहिया पार्किंग स्थल को निर्माण कार्यों के लिए स्थानांतरित किया गया है। रेलवे द्वारा यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि अपने दोपहिया वाहन एक्सप्रेसवे के पास निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें। यात्री स्टेशन परिसर अथवा अन्य अनधिकृत स्थानों पर अपने वाहन पार्क करने से बचें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यात्रियों की सुविधा के लिए गुडियारी साइड पर भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल में ही खड़ा करें तथा पार्किंग शुल्क की निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें। स्टेशन पुनर्विकास कार्यों के दौरान यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षित आवागमन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यात्रियों से अपील है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थल का ही उपयोग करें तथा रेलवे द्वारा लगाए गए संकेतकों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करें। रेलवे प्रशासन यात्रियों से सहयोग की अपेक्षा करता है। रायपुर स्टेशन के विकास एवं पुनर्विकास कार्यों को सुचारु रूप से पूरा करने में यात्रियों का सहयोग महत्वपूर्ण है।

## आयुष योगा वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा

रायपुर। आयुष विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु राज्य में वर्ष 2015 से 32 आयुष योगा वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य जन-जन तक योग की परंपरा को पहुंचाना तथा आधुनिक जीवनशैली में उत्पन्न तनाव, अवसाद एवं अस्वस्थता से मुक्ति दिलाना है। राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित योगा वेलनेस सेंटरों में प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों द्वारा योगासन, प्राणायाम, ध्यान, सूर्य नमस्कार, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आहार परामर्श जैसी गतिविधियाँ नियमित रूप से कराई जा रही हैं। इन केंद्रों में निःशुल्क नागरिकों को दैनिक योगाभ्यास की सुविधा दी जा रही है। योगा वेलनेस सेंटर न केवल स्वास्थ्य संवर्धन के केंद्र हैं बल्कि रोग से मुक्त जीवन की ओर जनआंदोलन के रूप में उभर रहे हैं।

## आयुक्त समित मिश्रा ने बताई रायपुर की नई कचरा व्यवस्था

## गीला-सूखा ही नहीं, 4 तरह से अलग होगा कचरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम को लेकर नगर निगम की तैयारी पूरी

रायपुर। ठोस कचरे के प्रबंधन को लेकर देश में लागू किए गए नए नियमों का असर अब शहरों के स्तर पर भी दिखाई देगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के नए प्रावधानों और रायपुर शहर में इनके नागरिक स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की कार्ययोजना को लेकर नगर पालिक निगम कार्यालय में पत्रकार-वार्ता आयोजित हुई। पत्रकार-वार्ता में नए नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ रायपुर में इनके जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और नागरिकों की भूमिका पर भी जानकारी दी गई।

नए नियमों के तहत कचरे का स्रोत पर ही चार श्रेणियों में पृथक्करण अनिवार्य किया गया है। रायपुर में भी नागरिकों को गीला कचरा, सूखा कचरा, स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल वाले कचरे को अलग-अलग रखने की व्यवस्था को प्रभावी बनाना होगा। घरों और संस्थानों से निकलने वाले कचरे को अगर शुरुआत में ही अलग कर दिया जाए तो उसके प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निपटान की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकेगी।

नए नियमों का सबसे सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। अब कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी केवल नगर निगम की नहीं होगी, बल्कि नागरिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी। घरों में गीले और सूखे कचरे को अलग रखने के साथ स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल वाले कचरे को भी निर्धारित तरीके से अलग करना होगा। इससे कचरे की संग्रहण के बाद अलग करने की जरूरत कम होगी और रिसाइक्लिंग तथा वैज्ञानिक प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा।

नए नियमों में बड़े यानी थोक कचरा उत्पादकों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां तय की गई हैं। 20 हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल, 40 हजार लीटर या उससे अधिक प्रतिदिन पानी की खपत, याा प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरा पैदा करने वाली संस्थाएं इस श्रेणी में आएंगी। रायपुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में बड़े आवासीय परिसरों, संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य बड़े कचरा उत्पादकों के लिए इन



प्रावधानों का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। थोक कचरा उत्पादकों को कचरे का प्रसंस्करण करना होगा। जहां यह संभव नहीं होगा, वहां निर्धारित व्यवस्था के तहत EBWGR प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। इसका उद्देश्य कचरे को उसके स्रोत के नजदीक ही संसाधित करना और नगर निगम की केंद्रीकृत व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव कम करना है। नए नियमों में ठोस कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग और निगरानी का प्रावधान है। कचरा पैदा होने से लेकर उसके संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और अंतिम निपटान तक की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से ट्रैक किया जा सकेगा। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिल सकती है। रायपुर में भी नए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डिजिटल निगरानी व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नए नियमों में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय मुआवजे का प्रावधान किया गया है। बिना पंजीकरण संचालन, गलत रिपोर्टिंग, जाली दस्तावेज और निर्धारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का उल्लंघन जैसे मामलों में

पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जा सकेगा। इससे कचरा प्रबंधन के नियमों के पालन को लेकर संस्थानों और संबंधित पक्षों की जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

रायपुर में कचरे की छंटाई और पुनर्चक्रण की व्यवस्था को मजबूत करने में Material Recovery Facility यानी MRF महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नए नियमों के तहत स्थानीय निकायों को कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि MRF के माध्यम से सूखे कचरे की छंटाई और उपयोगी सामग्री की रिकवरी को बढ़ावा दिया जाएगा।

नए नियमों का एक बड़ा उद्देश्य लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा कम करना है। लैंडफिल में केवल गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-ऊर्जा-पुनर्प्राप्ति योग्य और अक्रिय कचरा ही भेजे जाने का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि अगर घर और संस्थान स्तर पर कचरे का सही तरीके से पृथक्करण होता है, तो बड़ी मात्रा में कचरे को रिसाइक्लिंग और प्रोसेसिंग के लिए भेजा जा सकेगा

और लैंडफिल पर निर्भरता कम होगी।

नए नियमों में पुराने कचरा स्थलों के बायो-माइनिंग और बायो-रिमेडिएशन का प्रावधान किया गया है। ऐसे पुराने कचरा स्थलों का मानचित्रण और मूल्यांकन कर समयबद्ध तरीके से उपचार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसकी प्रगति की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का भी प्रावधान है। शहरों में लंबे समय से मौजूद पुराने कचरे के ढेरों के वैज्ञानिक उपचार की दिशा में यह महत्वपूर्ण व्यवस्था हो सकती है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को जमीन पर प्रभावी बनाने में नगर निगम की व्यवस्था के साथ नागरिकों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होगी।

घर से निकलते समय ही कचरे को अलग करना, निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कचरा देना, खुले कचरा न फेंकना और विशेष श्रेणी के कचरे को सामान्य कचरे में न मिलाना, ये ऐसे कदम हैं जिनसे नए नियमों के क्रियान्वयन को सीधे मजबूती मिलेगी।

## राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 मामलों पर हुआ मंथन

## 9 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी के संबंध में आज मंत्रालय में प्रकरण वापसी समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 प्रकरणों की वापसी से संबंधित मामलों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें 8 लंबित प्रकरण शामिल थे।

सभी मामलों में से 9 प्रकरणों की अनुशंसा की गई। दो प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए जिलों में भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त शेष मामलों को राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ ना पाते हुए उनको समिति ने विचार कर उन्हें अस्वीकृत कर दिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित प्रमुख सचिव गृह निहारिका बारीक, प्रमुख सचिव विधि मनीष ठाकुर, गृह सचिव नेहा चंपावत,



डीजीपी अरूण देव गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

समिति ने अधिकारियों से पूर्व में अनुशंसित लंबित प्रकरणों, उनकी वर्तमान स्थिति और नियमानुसार आगे की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली एवं इसकी नियमित समीक्षा करते हुए न्यायालय में लंबित प्रकरणों को भी त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से जुड़े मामलों की रामविचार नेताम सहित प्रमुख सचिव गृह प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाने के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की।

## 2 अक्टूबर से गांव-गांव में ‘रिफॉर्म उत्सव’ ग्राम सभा से बनेगा विकास का रोडमैप

रायपुर। पूरे छत्तीसगढ़ में 02 अक्टूबर 2026 से ‘रिफॉर्म उत्सव’ के साथ विकसित ग्राम पंचायत प्लान (बीजीपीपी) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जन योजना अभियान (पीपीसी) के साथ एकीकृत रूप से आयोजित होने वाले इस अभियान में ग्राम सभाओं को गांव के विकास की प्राथमिकताएं तय करने और योजनाओं पर सीधे संवाद का प्रमुख मंच बनाया जाएगा। ग्रामीणों से उनकी जरूरतों, विकास की कमियों, उपलब्ध संसाधनों और जरूरी कार्यों पर सुझाव लेकर इन्हें ग्राम पंचायत की आगामी विकास योजना में शामिल किया जाएगा।

रिफॉर्म उत्सव के दौरान ग्राम सभाओं में बीबी-जीरामजी के तहत 125 दिवस रोजगार की

वैधानिक गारंटी, 15 दिन में रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान, 375 अनुमेय कार्यों में से गांव की जरूरत के अनुसार कार्यों का चयन, आजीविका संवर्धन, ग्रामीण अधोसंरचना और विभिन्न योजनाओं के अभिसरण साथ साथ लखपति दीदी योजना , आजीविका गतिविधि जैसे विषयों पर ग्रामीणों से संवाद होगा। पंचायत प्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

बीजीपीपी के तहत 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में ग्रामीणों को योजना तैयार करने की प्रक्रिया, ग्राम पंचायत के आधारभूत आंकड़ों, आधार मानचित्र और उपलब्ध अनुमेय

कार्यों की जानकारी दी जाएगी।

गांव में मौजूद लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं परिसंपत्तियों की पहचान भी की जाएगी। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में बस्ती और वार्ड स्तर पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, स्थल सत्यापन और सामुदायिक परामर्श के माध्यम से स्थानीय जरूरतों और विकास संबंधी कमियों की पहचान होगी।

दिसंबर में तैयार बीजीपीपी का प्रारूप ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा। ग्रामीणों के सुझाव और विचार-विमर्श के बाद ग्राम सभा योजना को अनुमोदित करेगी। इसके बाद योजनाओं का विकासखंड और जिला स्तर पर समेकन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी की जाएगी।

## मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में स्टेट लेवल कमेटी की बैठक आयोजित

## ■ भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने भारत सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव

रायपुर। भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में बुधवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में स्टेट लेवल कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीआरडीए) द्वारा प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

बैठक में प्रस्तावित परियोजना के



डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मास्टर प्लान, भूमि उपलब्धता, आवश्यक अधोसंरचना, परियोजना लागत, वित्तीय व्यवस्था तथा की संचालन गाइडलाइन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा प्रस्ताव को भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

सीआरडीए द्वारा प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। लगभग 406.72 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस औद्योगिक पार्क में विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए

आवश्यक अधोसंरचना एवं सुविधाओं का विकास किया जाएगा। स्टेट लेवल कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे भारत सरकार को भेजे जाने के लिए अनुमोदित किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव को सीआरडीए, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों पर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी उमेश कुमार झा, एनआरडीए नवा रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन कुमार सहित कलेक्टर रायपुर वीरेंद्रियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे।

<

# ज्ञानेश के इस्तीफा से चुनाव व्यवस्था सुधर जायेगी?

#### नीरज कुमार दुबे

क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से देश की चुनावी व्यवस्था बदल जाएगी? क्या उनके पद से हटते ही मतदाता सूची की तमाम शिकायतें खत्म हो जाएंगी, क्या चुनाव में धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल रुक जाएगा, क्या राजनीति के अपराधीकरण पर लगाम लग जाएगी और क्या लोकतंत्र पहले से ज्यादा पारदर्शी हो जाएगा? यह सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की ओर से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है, उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी की बात सामने आ रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या समस्या सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त में है? सवाल उठता है कि अगर व्यवस्था की बुनियाद में ही खामियां हैं, तो फिर सिर्फ चेहरा बदलने से क्या बदलेगा? सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्यों न बहस उस कानून पर हो, जो भारत की चुनावी व्यवस्था की रीढ़ है यानि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951? और क्यों न पूछा जाए कि इस कानून में ऐसी कौन-सी खामियां हैं, जिन्हें दूर किए बिना भ्रष्टाचार, अपराध और धनबल से मुक्त राजनीति की कल्पना अधूरी ही रहेगी?
देखा जाये तो सवाल ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का नहीं, चुनावी व्यवस्था की बुनियाद का है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बदल जाएगा तो पूरी चुनाव व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या एक व्यक्ति के पद से हट जाने भर से मतदाता सूची की सारी विसंगतियां खत्म हो जाएंगी? क्या राजनीतिक दलों का टिकट बांटने का तरीका पारदर्शी हो जाएगा? क्या चुनाव में धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल रुक जाएगा? क्या आपराधिक मामलों का सामना कर रहे उम्मीदवार चुनावी मैदान से बाहर हो जाएंगे? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो फिर बहस केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे तक क्यों सीमित है? अभी हाल ही में सबने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा क्षेत्र की कुव्यवस्थाओं के खिलाफ हुए छात्रों के प्रदर्शन के चलते धर्मरं प्रधान को शिक्षा मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन क्या इससे शिक्षा व्यवस्था सुधर गयी? किसी मंत्री के इस्तीफे से यदि व्यवस्था अपने आप सुधर जाती, तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किसी दूसरी नीति, कानून, जवाबदेही और संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए चुनाव आयोग के मुखिया को बदलने की राजनीतिक मांग और चुनावी व्यवस्था में स्थायी सुधार, दोनों को एक ही चीज मानना गंभीर भूल होगी। असल बीमारी उस कानून में भी खोजनी होगी जो चुनाव लड़ने की पात्रता और अयोग्यता तय करता है। हम आपको बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनाव की योग्यता, अयोग्यता, नामांकन, मतदान, मतगणना, चुनाव अपराध, भ्रष्ट आचरण और चुनाव याचिकाओं जैसी पूरी व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। लेकिन जरा विडंबना देखिए। एक चपरासी की नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा चाहिए। भर्ती परीक्षा होती है। चरित्र और दस्तावेजों की जांच होती है। नियुक्ति के बाद सेवा नियम लागू होते हैं। गलती होने पर कार्रवाई होती है। लेकिन जो व्यक्ति देश की संसद में कानून बनाएगा, करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में भाग लेगा, उसके लिए मूल संवैधानिक शर्तें क्या हैं? भारतीय नागरिक होना, निर्धारित न्यूनतम आयु पूरी करना और मतदाता होना जैसी आवश्यकताएं हैं। यहां सवाल उठता है कि क्या जनप्रतिनिधि बनने के लिए सर्वजनिक जीवन का कोई न्यूनतम मानक नहीं होना चाहिए? इसके अलावा एक और प्रश्न आपराधिक राजनीति का है।

#### भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

## 10 जैन और चार्वाक

##### मातृक से आगे...

उनके धर्म सम्बन्धी सिद्धान्तों में बहुत बड़ा अन्तर है, परन्तु दार्शनिक सिद्धान्तों में यह अन्तर इतना अधिक है, कि जैन दर्शन की मौलिक रूपरेखा बौद्ध दर्शन की अपेक्षा न्यायवैशेषिक के अधिक समीप है।

उपर यह कहा गया है कि अनात्मवाद बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदायों की वैदिक दार्शनिक सम्प्रदायों से विभाजक रहा है। उस दृष्टि से जैनदर्शन न केवल प्राणियों में अलग आत्मा मानने के कारण, प्रत्युत बाह्य वस्तुओं को द्रव्य रूप में मानने के कारण भी बौद्ध दर्शन की अपेक्षा वैदिक दर्शनों के अधिक समीप आता है।

भारतीय दर्शनों में अतिराय रूप से भौतिकवादी केवल चार्वाक दर्शन ही है। वह ईश्वर, आत्मा आदि को तो मानता ही नहीं प्रत्युत राजनीतिक और पुनर्जन्म को भी नहीं मानता। और क्योंकि भारतीय धर्मों और दर्शनों में नैतिकता और सदाचार का आधार पुनर्जन्म

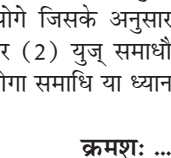
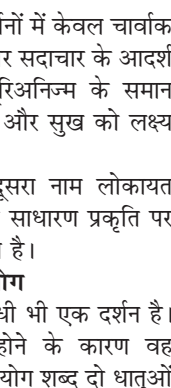
ही है, इस लिये सारे भारतीय दर्शनों में केवल चार्वाक ही ऐसा दर्शन है जो नैतिकता और सदाचार के आदर्श को पाश्चात्य दर्शन के एपीक्यूरअनिज्म के समान सर्वथा छोड़कर ऐंद्रियिक भोग और सुख को लक्ष्य बनाता है।

इसीलिये इस दर्शन का दूसरा नाम लोकायत अर्थात् लोक सामान्य लोगों की साधारण प्रकृति पर आश्रित (आयत-आश्रित) दर्शन है।

##### 11 भारतीय दर्शन और योग

वैदिक दर्शनों में योगसम्बन्धी भी एक दर्शन है। उसके निर्माता पातञ्जलि के होने के कारण वह पातञ्जलयोग दर्शन कहलाता है। योग शब्द दो धातुओं से बन सकता है- (1) युजियोगे जिसके अनुसार योग का अर्थ होगा जोड़ना और (2) युज् समधाी जिसके अनुसार योग का अर्थ होगा समाधि या ध्यान अर्थात् चित्त को एकाग्र करना।

**क्रमशः ...**



# ज्ञान/मीमांसा

# चुनाव आयोग पर उठते सवालों के बीच बड़े सुधार की जरूरत

#### आर जगन्नाथन

हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग (ईसीआई) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दो चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के बीच कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। इनमें मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा भी शामिल है। विपक्षी नेता, खासतौर पर राहुल गांधी, लंबे समय से चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाते रहे हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट से उन्हें अपने आरोपों के समर्थन में एक नया आधार मिला है। इसी वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठ रही है।

हालाँकि, चुनाव आयुक्तों को हटाना आसान नहीं है। उन्हें संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के जरिये ही हटाया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग की अपनी विश्वसनीयता के लिए जरूरी है कि वह इन सवालों पर अंदरूनी तौर पर गंभीर चर्चा करे और जनता को पारदर्शी तरीके से बताए कि वह किस तरह काम कर रहा है और भविष्य में ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाएगा। आयोग ने फिलहाल इतना ही कहा है कि उसके निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। लेकिन इससे पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। बेहतर होगा कि तीनों चुनाव आयुक्त एक साथ मीडिया के सामने आएँ और पत्रकारों के सवालों का जवाब दें। जरूरत हो तो वे अलग-अलग भी अपनी बात रखें। इससे लोगों के मन में उठ रहे संदेह काफी हद तक दूर हो सकते हैं।

इसके साथ ही, चुनाव आयोग पर पक्षपात का निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। यह समझना जरूरी है कि भारत जैसे विशाल देश में चुनाव व्यवस्था चलाना बेहद कठिन काम है। देश में करीब एक अरब मतदाता हैं और आयोग के पास सीमित संसाधन हैं। इसलिए हमें सिर्फ आरोप लगाने के बजाय यह सोचना चाहिए कि ऐसी समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है ताकि बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम गलती से मतदाता सूची से न हटें। मुख्य बात यह है कि हर समस्या के पीछे साजिश या पक्षपात मान लेना जरूरी नहीं है। कई बार व्यवस्था की जटिलता, कर्मचारियों की कमी और तकनीकी गलतियां भी किसी समस्या का कारण हो सकती हैं जिन पर एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी बात की गई है।



पहला कारण, निर्वाचन आयोग के दिल्ली स्थित मुख्यालय में स्थायी कर्मचारियों की संख्या लगभग 550 ही है। राज्यों में भी इसके स्थायी कर्मचारी बहुत ज्यादा नहीं हैं जबकि कई भारतीय राज्य ऐसे हैं जो अपने आकार और आबादी के लिहाज से दुनिया के कई देशों से बड़े हैं। चुनाव के समय आयोग राज्य सरकारों और दूसरी प्रशासनिक सेवाओं से करीब एक से सवा करोड़ अस्थायी कर्मचारियों की मदद ले सकता है। लेकिन चुनाव के पहले और बाद में मतदाता सूची को अपडेट करने जैसे कामों के लिए उसे काफी हद तक राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है।

पात्र मतदाताओं को जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं को इससे बाहर करने जैसे इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए तकनीक और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना स्वाभाविक है। लेकिन यही तकनीक कभी-कभी समस्या भी पैदा कर सकती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर यह तय करने लगे कि कौन मतदाता सूची में होना चाहिए और कौन नहीं, तो उसमें बड़ी संख्या में गलतियां हो सकती हैं। हालाँकि, इन गलतियों को बाद में ठीक किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाया जा सकता है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एसआईआर के कारण करीब 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटने की आशंका का उल्लेख किया गया है। यह संख्या पहली नजर में बहुत बड़ी लगती है। लेकिन इसे कुछ दो महत्वपूर्ण संख्या के संदर्भ में भी देखना चाहिए। भारत में हर साल करीब एक करोड़ लोगों की मृत्यु होती है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे बुजुर्गों की होती है जो मतदाता रहे होंगे।

दूसरी ओर, भारत में आंतरिक प्रवास करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। 2011 की जगणणना के अनुसार करीब 45.5 करोड़ भारतीय आंतरिक प्रवासी थे। आज वह संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। लोग नौकरी,

पढ़ाई या शादी जैसी वजहों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे में संभव है कि उनका नाम पुराने स्थान की मतदाता सूची में भी बना रहे और नए स्थान पर भी दर्ज हो जाए। जब लोग अपना स्थान बदलते हैं तब वे अक्सर पुराने पते से अपना नाम हटवाने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं करते।

मैं अपने निजी अनुभव की बात करूँ तो मैंने चार बड़े शहरों में काम किया और मैं इन शहरों के 13-14 अलग-अलग पते पर रहा हूँ। 30 वर्ष तक का होने तक मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं था और दो शहरों दिल्ली और कोलकाता में मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं था जबकि बाकी दूसरे शहरों में मैंने औपचारिक तौर पर अपना नाम हटवाने या पता बदलवाने की कोशिश नहीं की।

इसलिए संभव है कि मेरा नाम कुछ ऐसी मतदाता सूचियों में भी बना रहा हो, जहां मैं अब नहीं रहता हूँ। अगर एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों और दूसरे प्रवासियों के साथ ऐसा होना असामान्य नहीं है। इसलिए मतदाता सूचियों की समय-समय पर सफाई जरूरी है। साथ ही, 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके नए मतदाताओं के नाम भी जोड़ने होते हैं।

तीसरी बात, समस्या यह भी हो सकती है कि मतदाता सूची में दोहरे नाम या मृत लोगों के नाम खोजने वाला सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम न करे। इतने बड़े डेटाबेस की हर प्रविष्टि की ईमान द्वा़रा जांच करना मुश्किल है इसलिए सॉफ्टवेयर द्वारा किसी व्यक्ति के नाम या पते को संदिग्ध बताए जाने के बाद मानवीय जांच जरूरी है। भारत में नाम और पते अक्सर गलत लिखे जाते हैं।

एक ही नाम कई लोगों का हो सकता है और एक ही पते पर सैकड़ों लोग रह सकते हैं। इसलिए बिना ईसानी जांच के सिर्फ तकनीकी आधार पर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा देना उचित नहीं होगा।

चौथा, एसआईआर की एक आलोचना यह भी है कि इस प्रक्रिया में बहुत काम अवैध प्रवासियों के नाम सामने आए हैं जिनको मतदाता सूची से हटया गया है। पश्चिम बंगाल में अपील

के बाद जिन लोगों के नाम हटाए गए थे, उनमें से बड़ी संख्या के बारे में यह भी सामने आया कि वे अवैध प्रवासी नहीं थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या एसआईआर से वही काम करने की उम्मीद की जानी चाहिए जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का काम है?

पांचवां, एसआईआर जरूरी हो सकता है लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले इसे कराने से चुनाव आयोग और प्रशासन पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। चुनाव से ठीक पहले केवल सामान्य मतदाता सूची पुनरीक्षण होना चाहिए। व्यापक एसआईआर चुनाव के बाद, अगले विधान सभा या लोक सभा चुनाव से पहले पांच वर्षों के दौरान कराया जाना चाहिए।

इस पूरे विवाद से पांच महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली, सर्वोच्च न्यायालय को चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने चाहिए। यह साफ होना चाहिए कि आयोग महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमति कैसे बनाता है और अगर सहमति न हो तो मतदान कैसे होता है। बैठकों में किसने क्या कहा और किस आधार पर फैसला लिया गया, इसका रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए। इससे भविष्य में यह समझना आसान होगा कि किसी फैसले पर तीनों आयुक्तों की क्या राय थी।

दूसरी, चुनाव आयोग में स्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तीसरी, अगर चुनाव आयोग को मतदाता सूची से गैर-नागरिकों की पहचान करने की जिम्मेदारी नहीं दी जानी है, तो इसके लिए एनआरसी जैसे किसी तंत्र पर राजनीतिक सहमति बनाने की जरूरत होगी। ऐसा कोई अभ्यास कितने अंतराल पर हो, यह भी स्पष्ट रूप से तय किया जाना चाहिए।

चौथी, जब भी एसआईआर कराया जाए, राजनीतिक दलों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। केरल और तमिलनाडु में राजनीतिक दलों के सहयोग से यह काम अपेक्षाकृत सुचारु रूप से हुआ।

पांचवीं, मृत लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए मृत्यु पंजीकरण के रिकॉर्ड को मतदाता सूची से जोड़ने का कोई प्रभावी तरीका बनाया जाना चाहिए। इसलिए इससे पहले कि लोग यह निष्कर्ष निकालें कि चुनाव आयोग का रवैया विपक्ष के साथ अनुचित रहा है, इन बदलावों पर काम करना शुरू करना होगा ताकि आयोग पूरी क्षमता और पारदर्शिता के साथ काम कर सके।

## राजघराने से ताल्लुक रखते थे एसडी बर्मन, ऐसे बने प्रतिष्ठित संगीतकार

#### अनन्या मिश्रा

भारतीय सिनेमा संगीत जगत में अहम भूमिका निभाने वाले एसडी बर्मन का 01 अक्टूबर को जन्म हुआ था। एसडी बर्मन सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर थे। उनका असली नाम सचिन देव बर्मन था। एसडी बर्मन बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी थे, उनकी खासियत यह थी कि वह किसी भी परिस्थिति के मुताबिक म्यूजिक बनाकर तैयार कर लेते थे। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी मान लेना जरूरी नहीं है। कई बार व्यवस्था की जटिलता, कर्मचारियों की कमी और तकनीकी गलतियां भी किसी समस्या का कारण हो सकती हैं जिन पर एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी बात की गई है।

त्रिपुरा के शाही परिवार में 01 अक्टूबर को सचिव देव बर्मन का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम एमआरएन देव था, जोकि एक जाने-माने सितारावादक और ध्रुपद थे। उनकी मां का नाम निर्मला देवी

था, जो मणिपुर की राजकुमारी थी। लेकिन इसके बाद भी एसडी बर्मन बहुत सरल जीवन जीते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पूरी की और फिर साल 1931 में कोलकाता के रेडियो स्टेशन में गायक के रूप में जुड़े थे।

एसडी बर्मन ने अपने संगीत करियर की शुरुआत 1937 में की थी। धीरे-धीरे उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी संगीत करियर की शुरुआत की थी। हिंदी और बंगाली फिल्मों को मिलाकर करीब 100 फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा है। इस फिल्मों के लिए एसडी बर्मन ने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, तलत मेहमूद जैसे शानदार



फिल्मों के लिए गाते गए थे। फिर साल 1944 में वह मुंबई आ गए और दो साल बाद यानी की साल 1946 में एसडी बर्मन को फिल्म शिकारी और 8 दिन में संगीत देने का मौका मिला। इसके बाद एसडी बर्मन को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी।

एसडी बर्मन ने 100 से अधिक फिल्मों में म्यूजिक देने के साथ 14 हिंदी फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी थी। इसमें

गायकों के साथ काम किया। एसडी बर्मन के बेटे आरडी बर्मन ने भी संगीत जगत में अपने शानदार गाने दिए हैं। बता दें कि एसडी बर्मन ने बतौर सितार वादन संगीत की दुनिया में कदम रखा था। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई हिंदी और बांाला

फिल्मों के लिए गाते गए थे। फिर साल 1944 में वह मुंबई आ गए और दो साल बाद यानी की साल 1946 में एसडी बर्मन को फिल्म शिकारी और 8 दिन में संगीत देने का मौका मिला। इसके बाद एसडी बर्मन को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी।

एसडी बर्मन ने 100 से अधिक फिल्मों में म्यूजिक देने के साथ 14 हिंदी फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी थी। इसमें

### आज का इतिहास

- 1854 भारत में डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। टिकट पर महारानी विक्टोरिया का सिर और भारत बना होता था। इसकी कीमत आधा आना (1/32 रुपये) थी।
- 1919 हन्टर समिति की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 अक्टूबर, 1919 ई. को की गई थी।
- 1949 चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की शुरुआत हुई।
- 1949 जनरल माओ-त्से-तुंग द्वारा चीन जनवादी गणराज्य (पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना) की घोषणा।
- 1953 आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना।
- 1960 नाइजीरिया यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ।
- 1967 भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई।
- 1978 लड़कियों की शादी की उम्र को 14 से बढ़ा कर 18 और लड़कों का 18 से बढ़ा कर 21 वर्ष किया गया।
- 1996 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा पश्चिम एशिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन।
- 1998 श्रीलंका में किलिनोच्ची एवं मानकुलम शहरों पर कब्जे के लिए सेना एवं लिटेरे उगवादियों के बीच हुए संघर्ष में 1300 लोगों की मृत्यु।
- 2002 एशियाड खेलों में झूकर प्रतिस्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ।
- 2003 नदियों को जोड़ने के सम्बन्ध में बांग्लादेश की आशंकाओं को भारत ने दूर किया।
- 2004 इज़रायली प्रधानमंत्री एरियल शैरोन के मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई की योजना को मंजूरी दी।
- 2005 इंडोनेशिया के बाली में हुए बम विस्फोट में 40 लोगों की मृत्यु।
- 2006 इज़रायल ने लेबनान से अपनी सेना की आखिरी टुकड़ी को भी वापस बुलाया।
- 2007 जापान ने उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबन्धों को अगले छ महीनों तक बढ़ाने की घोषणा की।
- 2008 आतंकवादियों ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बम ब्लास्ट किया।
- 2015 ग्वाटेमाला के संत काटरीना पिनुला में भारी बारिश और भूस्खलन से 280 लोगों की मौत।
- 2017 लूस वेगास में 64 वर्ष के एक बंदूकधारी ने संगीत समारोह में गोलीबारी कर 58 लोगों की जान ली और फिर खुद को भी गोली मार ली।
- 2020 महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्वदेश निर्मित लेजर गाइडेड टैंक भेदी मिसाइल (एटीजीएम) का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सफल परीक्षण किया।

# मतदाता सूची स्वच्छ बनाएं, मगर वैध मतदाताओं के नाम न हटाएं

## पूनम आई. कौशिश

लोकतंत्र की शुरुआत एक सरल प्रश्न से होती है– मतदान करने का अधिकार किसे है? मुझे निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का पहला अनुभव अपने ही घर के दरवाजे पर हुआ। एक बुध-स्तरीय अधिकारी मेरे निर्वाचन संबंधी विवरणों का सत्यापन करने आए। मैंने उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 2 मतदाता पहचान-पत्र (1995 और 2009 के) दिखाए और सोचा कि यह पर्याप्त होगा लेकिन, जाहिर तौर पर ऐसा नहीं था। मुझे बताया गया कि चूंकि मेरे पास वर्ष 2002 का मतदाता पहचान-पत्र नहीं है, इसलिए मुझे सुनवाई के लिए उपस्थित होना होगा। ‘क्यों?’ इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। न ही यह समझाया गया कि 2002 का कार्ड ऐसा कौन-सा जादुई दस्तावेज है, जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए 2 मतदाता पहचान-पत्रों से वह बात सिद्ध कर सकता है, जो वे दोनों मिलकर नहीं कर सकते।

यही छोट्टा-सा अनुभव विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की बड़ी समस्या को सामने लाता है। संक्षेप में, जब कोई नागरिक कोई सरल प्रश्न पूछता है, तो संस्था के पास उसका स्पष्ट उत्तर होना चाहिए। अन्यथा मतदाता सूची को साफ करने की एक सामान्य प्रक्रिया कुछ और बन जाती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नागरिकों को चुनावी नौकरशाही के रास्तों को समझकर आगे बढ़ना पड़ता है। यही कारण है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को लेकर पैदा हुआ विवाद केवल

मतदाता सूचियों की सफाई का एक प्रशासनिक अभ्यास नहीं है। यह लोकतांत्रिक सामाजिक अनुबंध के मूल तक जाता है। देशभर में मसौदा मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि ऐसा मृत, दोहरें, स्थानांतरित और अपात्र प्रविष्टियों को हटाकर सटीक मतदाता सूचियां सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह एक वैध संवैधानिक उद्देश्य है। चुनाव में फर्जी मतदाता के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। मृत मतदाता मतदान नहीं कर सकता लेकिन यदि किसी वास्तविक मतदाता का नाम हटा दिया गया है, तो वह भी मतदान नहीं कर सकता। यहीं खतरे की घंटी बजती है। मुद्दा यह है कि क्या सफाई की यह प्रक्रिया अनजाने में वास्तविक मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित कर सकती है, विशेषकर तब, जब इस प्रक्रिया में लाखों नाम, जटिल दस्तावेज और कम समय-सीमा शामिल हों।

मतदाता सूची को साफ करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की नियमित व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन नागरिकों से यह प्रमाणित करने के लिए कहना कि उन्हें सूची में बने रहने का अधिकार क्यों है, एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रक्रिया है। एक और चिंताजनक घटनाक्रम निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेद से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 2 निर्वाचन आयुक्तों-संघू और जोशी ने 10 महीनों में चुनावी सूची संबंधी प्रक्रिया के फैसलों और उपायों पर 14 बार आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें नए मतदाताओं के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में किए गए बदलाव भी शामिल थे, जिनमें आवेदक अथवा



उसके माता-पिता की पूर्व एस.आई.आर. सूचियों में उपस्थिति से संबंधित प्रश्न जोड़े गए थे। दोनों ने इन्हें ‘अवैध’ और ‘अनुधिकृत’ बताया। निश्चित रूप से यह कोई मामूली असहमति नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग कोई ऐसा सामान्य सरकारी विभाग नहीं है, जहां आंतरिक असहमति किसी फाइनल में दबकर रह जाए। वह चुनावों का संवैधानिक निर्णायक है।

आयोग ने जवाब दिया कि विचारों में मतभेद विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं और एस.आई.आर. से जुड़े निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अपने सहयोगियों को ‘दरकिनार’ किए जाने का आरोप अपने आप में एक प्रश्न बना हुआ है। हालांकि, इससे एक बड़ा प्रश्न सामने आता है-तीन सदस्यीय संवैधानिक निकाय के 2 सदस्यों ने सार्वजनिक

संसद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक और नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मतदाता सूची का राजनीतिकरण किया गया है और एस.आई.आर. को इस तरह तैयार किया गया है कि इससे भाजपा के पक्ष में चुनावी परिणाम प्रभावित हों। निर्वाचन आयोग इन आरोपों को खारिज करता है। लेकिन आयोग को यह समझना चाहिए कि पारदर्शिता संदेह का सबसे अच्छा उपचार है। उसे आंकड़े, कार्यप्रणाली, नाम हटाने के कारण, प्राप्त आपत्तियों की संख्या और कितनी आपत्तियां स्वीकार या अस्वीकार की गईं तथा क्यों, इन सबका विवरण प्रकाशित करना चाहिए। इसके साथ ही आयोग के सदस्यों के बीच हुए मतभेदों और उनके समाधान की प्रक्रिया भी स्पष्ट की जानी चाहिए।

स्वतंत्र चुनावों के लिए स्वच्छ मतदाता सूची जरूरी है। लेकिन मतदाता सूची को केवल इसलिए स्वच्छ नहीं कहा जा सकता कि उसमें से लाखों नाम गायब हो गए हैं। वह तभी स्वच्छ है जब प्रत्येक पात्र नागरिक, जो मतदान करना चाहता है, उसके पास सूची में अपना नाम बनाए रखने का निष्पक्ष और व्यावहारिक अवसर हो। इसलिए निर्वाचन आयोग को विपक्ष, न्यायालयों और नागरिकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि उसका अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि उसे अपारदर्शी नहीं होने दिया जा सकता। चुनाव आयोग को राजनीतिक संघर्ष के मैदान से ऊपर खड़ा होना होगा, क्योंकि चुनाव न तो सरकार की संपत्ति हैं और न विपक्षी दलों की। वे मतदाताओं के हैं।

यदि लाखों मतदाताओं के नाम सूचियों से गायब हो जाते हैं और स्वयं निर्वाचन आयोग के भीतर इस बात पर मतभेद हो कि प्रक्रिया किस प्रकार संचालित की जा रही है, तो सवाल केवल यह नहीं रह जाता कि चुनाव कौन जीतेगा। इससे भी अधिक मूलभूत प्रश्न यह है-क्या किसी चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कहा जा सकता है, यदि हमें निश्चित न हों कि प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी गई थी? क्योंकि यदि मतदाता सूचियां ही सवालों के घेरे में हों, तो चुनावी जनादेश पर भी अनिवार्य रूप से प्रश्नचिह्न लग जाता है। और जब स्वयं 2 निर्वाचन आयुक्त प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट उत्तर चाहते हैं लेकिन उन्हें इसकी बजाय अस्पष्ट और शब्दांडंबरपूर्ण स्पष्टीकरण मिलते हैं, तो चिंता केवल राजनीतिक नहीं रह जाती।

## प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जेन-जी की शैली अपनाई!

### हरीश गुप्ता

भाजपा ने शायद एक नया राजनीतिक मंत्र खोज लिया है: अगर समय को नहीं बदल सकते, तो स्पेलिस्ट ही बदल डालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में दिल्ली में आरएसएस द्वारा दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित युवाओं से भरी भजन-सभा में उपस्थिति मात्र एक धार्मिक आयोजन से कहीं अधिक थी। युवा भजन प्रेमियों के बीच बैठे प्रधानमंत्री भी भजन में शामिल हो गए। दृश्य स्पष्ट था – मोदी अपने सामान्य राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि उस पीढ़ी से घिरे हुए थे जिसने उन्हें केवल उन वरिष्ठ नेताओं से घिरे प्रधानमंत्री के रूप में देखा है जो हर समय राष्ट्र को उपदेश देते रहते हैं। और इस जेन-जी पहुंच की अपनी एक साउंडट्रैक भी है। वडोदरा में एक युवा कार्यक्रम के दौरान मोदी की नाटकीय एंट्री हुई और पूष्ठभूमि में क्रीन का ‘वी विल रॉक यू’ बज रहा था। साफ है कि भाजपा पारंपरिक राजनीतिक शब्दावली से आगे बढ़कर भी प्रयोग कर रही है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नंदीन ने इस कवायद को एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने हाल में 44 युवा नेताओं और मंत्रियों के साथ चार घंटे का विचार-मंथन सत्र किया, जिसमें छात्रों और युवाओं से जुड़ने के तरीकों पर चर्चा हुई। इसमें भाजयुमो प्रमुख हेमंत जोशी और पूर्व अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, पूनम महाजन और अनुराग ठाकुर के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिया कुमारी भी शामिल थीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को युवा नेताओं से मिल रहे सुझावों को ध्यान से नोट करते देखा गया। दिलचस्प यह कि एक शब्द को सख्ती से चर्चा से बाहर रखा गया- ‘जेन-जी’। इसके बजाय ‘छात्र’ और ‘युवा’ जैसे शब्दों को प्राथमिकता दी गई। शायद भाजपा भी जानती है कि कभी-कभी जेन-जी को लुप्ताने का

सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि उसे जेन-जी न कहा जाए।

**प्रियंका की नई भूमिका को लेकर संस्पेंस:** कांग्रेस के भीतर इन दिनों यह चर्चा तेज है कि प्रियंका गांधी बाइको जल्द ही पार्टी संगठन में बड़ी और अधिक स्पष्ट भूमिका सौंपी जा सकती है। अटकलों को तब और बल मिला जब उन्होंने हाल ही में राहुल गांधी के साथ एआईसीसी सचिवों के साथ हुई बैठकों में हिस्सा लिया। इन बैठकों में सचिवों के कामकाज की समीक्षा के साथ-साथ पार्टी के जमीनी फीडबैक तंत्र का आकलन किया गया। आमतौर पर ऐसी संगठनात्मक समीक्षा राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर करते रहे हैं। ऐसे में इस बार प्रियंका की भागीदारी ने पार्टी के भीतर चर्चाओं को हवा दे दी है। राहुल और प्रियंका ने पदाधिकारियों से संगठन से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत फीडबैक लिया, खासकर इस बात पर कि जमीनी स्तर से सूचनाओं का प्रवाह कैसे तेज किया जाए। और पार्टी की प्रतिक्रिया प्रणाली को कैसे बेहतर बनाया जाए। प्रियंका लगभग चार वर्षों से एआईसीसी की महासचिव हैं, लेकिन उनके पास कोई विशिष्ट विभाग नहीं है। उनकी आखिरी बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी 2022 में उत्तर प्रदेश की थी। यह नया रहस्य 5 सितंबर को हुए एआईसीसी महासचिवों के फेरबदल के बाद और गहरा गया। इस फेरबदल में सभी महासचिवों को जिम्मेदारियां बांट दी गई – सिवाय प्रियंका गांधी और मुकुल वासनिक के। वासनिक को गुजरात का प्रभार गंवाने के बाद भी बिना किसी विभागे के बरकरार रखा गया है। दो रिक्रि पदों के कारण यह अटकलें तेज हो गई हैं कि प्रियंका के लिए कुछ अधिक सुनियोजित भूमिका तैयार की जा रही है।

## सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत को मजबूत राजनयिक प्रयास करने होंगे

### कल्याणी शंकर

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) में स्थायी और अस्थायी दोनों सीटों के लिए मुहिम चला रहा है। स्थायी सीट हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में महत्वपूर्ण बदलावों की आवश्यकता है, जो धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत को ‘ग्लोबल साऊथ’ और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख आवाज के रूप में देखा जाता है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर, जो संयुक्त राष्ट्र की बैठक के लिए न्यूयॉर्क में हैं, ने इस साल अस्थायी सीट के लिए अभियान शुरू किया है। अगस्त 1950 में, अमरीका ने अपने राजदूत के माध्यम से भारत को यू.एन.एस.सी. में चीन की जगह भारत को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया था। कहा जाता है कि नेहरू ने इस सुझाव को खारिज कर दिया था, जिससे भारत ने स्थायी सदस्यता का मौका गंवा दिया।

नई दिल्ली अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों के तहत पिछले 30 वर्षों से इस सीट के लिए काम कर रही है। वर्षों से, कई देशों ने भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है, उसकी बढ़ती हुई प्रभाव क्षमता, बड़ी जनसंख्या और शांति स्थापना में योगदान को मान्यता दी है। हालांकि, यू.एन.एस.सी. के ढांचे को बदलना जटिल है क्योंकि इसके लिए वर्तमान 5 स्थायी सदस्यों-अमरीका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है। भारत का मानना ​​है कि वर्तमान यू.एन.एस.सी. ढांचा अब आधुनिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता। इसका तर्क है कि सबसे बड़े लोकतंत्र और बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति इसे एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनाती है। शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में उसकी महत्वपूर्ण भागीदारी के माध्यम से दिखाई देती है, जहां उसने स्थिरता बनाए रखने में मदद करने के लिए कई कर्मियों को भेजा है।

भारत को मजबूत राजनयिक प्रयासों में संलग्न होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ताजिकिस्तान भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एशिया-प्रशांत अस्थायी सीट के लिए होड़



कर रहा है। इस्लामिक सहयोग संगठन (ओ.आई.सी.) से ताजिकिस्तान को मिलने वाला समर्थन भारत के लिए प्रतिस्पर्धा को और कठिन बना सकता है। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, भारत को फिजी, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया तथा श्रीलंका से परे और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। चुनाव साल में एक बार गुप्त मतदान के माध्यम से होते हैं और इसके लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, भले ही उम्मीदवार निर्विरोध हों।

कुछ यूरोपीय देश यू.एन.एस.सी. के लिए भारत की बोली का समर्थन करते हैं। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, जिसमें कितनी नई सीटें जोड़नी हैं और उन नए सदस्यों के लिए वीटो पावर के विवादस्पद प्रश्न पर असहमति शामिल है। विभिन्न देशों के समर्थन के बावजूद, भारत को नई सीटों और वीटो पावर को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह एक ऐसे प्रस्ताव का पक्षधर है, जो शुरू में नए स्थायी सदस्यों के लिए वीटो अधिकारों को बाहर करता है, जिससे मौजूदा सदस्यों की चिंताओं को संबोधित किया और साथ ही निष्पक्ष प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जा सके।

जैसा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसदीय सत्रों में दोहराया है, भारत यू.एन.एस.सी. सुधारों पर अंतर-सरकारी वार्ता में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। भारत यू.एन.एस.सी. के विस्तार के लिए व्यापक समर्थन जुटाने के लिए काम कर रहा है। इस रणनीतिक जुड़ाव में ‘ग्लोबल साऊथ’ देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने, सामूहिक विकास को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांझी चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत

की प्रतिबद्धता को उजागर करना शामिल है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की कवालत करता है क्योंकि उसका मानना ​​है कि वर्तमान ढांचा अब 21वीं सदी की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कई यूरोपीय देशों ने भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है, इसे परिषद के भीतर प्रतिनिधित्व में विविधता लाने के एक तरीके के रूप में देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुधार की तत्काल आवश्यकता के बारे में विशेष रूप से मुखर रहे हैं, उन्होंने सीट आबंटन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के दावों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया है। हालांकि, सुधार प्रक्रिया को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है क्योंकि कोई एकीकृत वार्ता पाठ मौजूद नहीं है और विस्तारित सदस्यता और वीटो पावर के विवादस्पद मुद्दे पर विवाद जारी है। कई देशों से मजबूत समर्थन के बावजूद, महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। इन चुनौतियों के केंद्र में नई सीटों के आबंटन और अतिरिक्त सदस्यों को वीटो पावर का उपयोग करने की अनुमति देने के निहितार्थों पर विवादस्पद चर्चाएं हैं। फिर भी, भारत स्थायी सदस्यता की कवालत करना जारी रखे हुए है, वैश्विक शासन और शांति और सुरक्षा के उन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है, जिन्हें यू.एन.एस.सी. को बनाए रखना है।

भारत के लिए समर्थन लगातार बढ़ रहा है, जिसमें अफ्रीकी संघ जैसी संस्थाओं का समर्थन शामिल है, जिसने यह सुनिश्चित करने के लिए स्थायी सीट की मांग की है कि यू.एन.एस.सी. अफ्रीकी हितों और दृष्टिकोणों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करे। फिर भी, स्थायी सदस्यता का मार्ग जटिल है और इसके लिए वर्तमान स्थायी सदस्यों के बीच सावधानीपूर्वक बातचीत और आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। यह बोली क्षेत्रों में, विशेष रूप से ‘ग्लोबल साऊथ’, ओ.आई.सी. सदस्यों, एस.सी.ओ. देशों, अफ्रीकी राज्यों, द्वीपीय देशों और प्रमुख पश्चिमी भागीदारों के बीच भारत की राजनयिक पहुंच का परीक्षण करेगी।

## ज्यादा जरूरी है भरोसे की सूची, चुनाव आयोग सरकारी विभाग नहीं

### राजीव शुक्ला

चुनाव आयोग से एक सीधा सवाल है कि आपका काम क्या है? मतदाता सूची में मेरे हुए लोगों के नाम हैं, तो हटाइए या एक आदमी का नाम दो जगह है, तो ठीक कीजिए, जो कहीं और चला गया है, उसका पता बदलिए या नए मतदाता आए हैं, तो उन्हें जोड़िए। देश की जनता को इससे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन अगर मतदाता सूची सुधारने की प्रक्रिया इतनी बड़ी हो जाए कि करोड़ों लोगों को अपने ही वोट का हिसाब देना पड़े, तो सवाल उठेगा और उनके जवाब भी देने पड़ेंगे। चुनाव आयोग उस घर का रखवाला है, जिसे ‘लोकतंत्र’ का नाम दिया गया है और आयोग का काम यह देखना है कि किसी का वोट चोरी न हो, किसी का नाम गलत तरीके से न कटे और कोई ऐसा व्यक्ति मतदान न कर पाए, जिसे कानूनन अधिकार नहीं दिया गया है। एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची की जांच चल रही है और आयोग कहता है कि इसका मकसद सूची को साफ करना है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में केवल मकसद नहीं देखा जाता, तरीका भी देखा जाता है। एक राज्य में यदि एक पार्टी तीन लाख मतों के अंतर से जीत रही है और आपने एक जांच के नाम पर इकतीस लाख वोट हटा दिए, तो इसका क्या अर्थ होगा? क्योंकि वोट कोई सरकारी कागज नहीं है, जिसे गलती से काट दिया और बाद में जोड़ दिया। वोट उस आम आदमी की ताकत है, जिसके पास सत्ता के दरवाजे तक पहुंच नहीं है। इसलिए सवाल यह है कि मतदाता सूची की सफाई करते समय कहीं मतदाता ही तो नहीं साफ हो रहे? विपक्ष यह सवाल लगातार उठा रहा है कि प्रक्रिया के बहाने सही भारतीयों को भी वोट से बाहर करने का रास्ता बनाया जा रहा है। इसे सरकार और चुनाव आयोग खारिज कर सकते हैं, पर आरोप को राजनीतिक बताकर खारिज कर देना कहां की जवाबदेही और जिम्मेदारी है? आप आंकड़े सामने रखिए कि कितने नाम हटे? क्यों हटे? कितने लोगों ने आपत्ति की? कितनों की आपत्ति सही निकली? कितने नाम वापस जोड़े गए? कितने लोग ऐसे रहे, जो प्रक्रिया पूरी ही नहीं कर पाए? और मतदान वाले राज्यों में यह प्रक्रिया



चुनावों से कितनी पहले पूर्ण हुई? दिल्ली में लाखों मतदाताओं को नोटिस दिए गए हैं। आयोग का कहना है कि नोटिस का अर्थ नाम काटना नहीं है। लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। यह बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिसे नोटिस मिला है, उससे एक बार गांव की भाषा में पूछिए कि उसे यह प्रक्रिया कितनी आसान लगती है। जिस मजदूर ने पांच शहर बदल दिए, वह हर जगह का रिकॉर्ड कहां से लाएगा? जिस बुजुर्ग को अपने माता-पिता के पुराने दस्तावेज तक याद नहीं, वह किस दफ्तर में जाएगा? दिल्ली में बैठकर फाइल पर लिखा जा सकता है कि नागरिक को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा, लेकिन लोकतंत्र की अस्पली लड़ाई फाइल में नहीं, गरीब आदमी के दरवाजे पर होती है। यहीं चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि किसी गलत नाम को हटाना प्रशासन की सफलता हो सकती है, पर किसी सही नागरिक का नाम काट जाना सिर्फ प्रशासन की गलती नहीं रह जाती। वह नागरिक के अधिकार का सवाल बन जाती है। दस महीने में दो चुनाव आयुक्त 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज करते हैं, तो कहा जाता है कि बहुमत से फैसला होना कानून की व्यवस्था है, पर बहुमत कोई जादुई शब्द नहीं है, जिससे हर सवाल खत्म हो जाए। अगर दो आयुक्त बार बार किसी प्रक्रिया पर आपत्ति कर रहे हैं, तो उसका विवरण जानने का अधिकार सबको है। सबसे बड़ा खतरा

यही है कि बहुमत के नाम पर सवाल पूछना ही बेकार समझ लिया जाए। जहां तक सॉफ्टवेयर का सवाल है, करोड़ों मतदाताओं का रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम पर है। यह जरूरी भी है। इतनी बड़ी आबादी की मतदाता सूची कंप्यूटर के बिना संभालना मुश्किल है, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार को सिर्फ सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सॉफ्टवेयर गलती कर सकता है, डाटा गलत जा सकता है, किसी अधिकारी का फैसला दर्ज करने में असफल हो सकता है, तब उसका नुकसान किसे होगा? तकनीक की मदद के लिए है, न कि व्यवस्था, तकनीक की मदद के लिए। कंप्यूटर के लिए एक नाम डाटा है और हमारे लिए वह नाम एक इंसान है। इसीलिए, चुनावी आईटी व्यवस्था पर स्वतंत्र जांच, साफ जवाबदेही और मानवीय निगरानी जरूरी है।

आयोग किसी सरकार का विभाग नहीं है। उसे किसी सरकार के पक्ष में नहीं होना चाहिए और किसी विपक्ष के पक्ष में भी नहीं। उसकी निष्ठा सिर्फ संविधान और मतदाता के प्रति होती है, लेकिन स्वतंत्र संस्था होने का मतलब जवाबदेही से जुड़े सवालों से मुक्त होना नहीं होता। लिहाजा, चुनाव आयोग को आलोचना से बचने की नहीं, बल्कि पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है। किसी नागरिक का नाम काटिए, तो कारण बताइए, नोटिस दीजिए, तो भाषा ऐसी रखिए, जिसे गांव का आदमी समझ सके, कागज मॉर्गिए, तो बताइए कि कौन-सा दस्तावेज और गलती हो, तो जल्दी सुधारिए, सॉफ्टवेयर का फैसला इन्सानी जांच से ऊपर मत रखिए और आयोग के भीतर गंभीर आपत्तियां उठें, तो उनका जवाब रिकॉर्ड पर रखिए। यह लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी ताकत उसकी कानूनी शक्ति नहीं, बल्कि जनता का भरोसा है। अगर नागरिकों के मन में यह बैठ गया कि चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उस भरोसे को वापस लाना किसी सरकारी आदेश से संभव नहीं होगा।

## सर्जिकल स्ट्राइक की उस रात भारत ने दुश्मनों को कर दिया था स्पष्ट

### नीरज कुमार दुबे

दस साल पहले 28-29 सितंबर की रात भारत ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवाद के उन ठिकानों पर प्रहार किया था, जिन्हें लंबे समय से सीमा पार आतंक की मशीनरी का हिस्सा माना जाता रहा था। यह केवल कुछ आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की सुरक्षा नीति में एक निर्णायक मोड़ था। उरी हमले में 19 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद हुई 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक ने यह संकेत दिया था कि सीमा पार से आतंकवाद को केवल कूटनीतिक या सीमित सैन्य प्रतिक्रिया तक सीमित रखने का पुराना ढांचा बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सप्ताह यानि 27 सितंबर 2026 को ‘मन की बात’ में इसी बदलाव को रेखांकित करते हुए 2016 की कार्रवाई को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया था। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हैं, यह देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। प्रधानमंत्री ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को बालाकोट और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए भारत की आतंकवाद विरोधी नीति में लगातार आए बदलाव को सामने रखा था। देखा जाये तो असल बदलाव समझने के लिए 2016 से पहले की तस्वीर देखनी होगी। संसद हमले और 2008 के मुंबई हमले जैसे बड़े आतंकवादी हमलों के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी रणनीतिक दुविधा यही थी कि पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकवाद का सैन्य जवाब देने पर कहीं दो परमाणु-संपन्न देशों के बीच व्यापक युद्ध न छिड़ जाए। इसी आशंका ने लंबे समय तक भारत की नीति को संयम की सीमा में रखा। लेकिन उरी ने इस गणित को बदल दिया। 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय विशेष बलों ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार ने इस कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि आतंकवाद और उसके बुनियादी ढांचे के बीच दूरी बनाकर भारत को रोकने की रणनीति अब पहले जैसी प्रभावी नहीं मानी जाएगी। यहीं से भारत की प्रतिरोधक रणनीति का नया अध्याय शुरू हुआ। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में हवाई कार्रवाई ने जवाब की भौगोलिक सीमा को नियंत्रण रेखा से आगे बढ़ाया। यानी

2016 में जहाँ जमीनी कार्रवाई नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों तक पहुँची थी, वहीं बालाकोट एअर स्ट्राइक ने यह दिखाया कि भारत आवश्यकता पड़ने पर पाकिस्तान के भीतर भी आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। फिर 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने इस रणनीति को एक और स्तर पर पहुँचा दिया। 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। मोदी सरकार ने इसे केंद्रित और नियंत्रित कार्रवाई बताया तथा कहा कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया। यानी उरी, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर, यह तीनों एक जैसी सैन्य कार्रवाइयों नहीं थीं। इनके तरीके, हथियार, लक्ष्य और भौगोलिक दायरे अलग थे। लेकिन इनके पीछे दिखाई देने वाला रणनीतिक संदेश एक ही था कि भारत आतंकवादी हमले और उसके पीछे मौजूद बुनियादी ढांचे को पूरी तरह अलग-अलग घटनाएँ मानकर नहीं चलेगा। इस तरह 2016 का अभियान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सोच में निर्णायक बदलाव था। भारत ने तथाकथित ‘रणनीतिक संयम’ से आगे बढ़कर ऐसी प्रतिरोधात्मक कार्रवाई की दिशा पकड़ी जिसमें पूर्ण युद्ध की सीमा पार किए बिना अपनी क्षमता दिखाई गई। यही इस बदलाव का सबसे बड़ा रणनीतिक अर्थ है। इसका निशाना केवल आतंकवादी संगठन नहीं, बल्कि प्रॉक्सी युद्ध का पूरा गणित है। हालाँकि भारत की कार्रवाइयों के बावजूद प्रॉक्सी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। खतरे ने अपना रूप बदला है। झोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थ भेजना, छोटे प्रशिक्षित घुसपैठ दल और कम दृश्यता वाली आतंकवादी कार्रवाइयाँ इसी बदलती रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं। जम्मू क्षेत्र और पीर पंजाल के दक्षिण में बढ़ा सुरक्षा फोकस भी इसी बदलाव को दर्शाता है। बहरहाल, दस साल पहले सवाल था कि आतंकी हमले के बाद भारत जवाब देगा या नहीं? उरी के बाद वह सवाल बदल गया। अब सवाल यह है कि जवाब किस स्तर पर होगा, उसकी सीमा क्या होगी और आतंकवाद के पीछे मौजूद ढांचे पर उसकी कीमत कितनी भारी पड़ेगी। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक ने इस बदलाव को दृश्यमान किया; बालाकोट ने उसे आगे बढ़ाया और ऑपरेशन सिंदूर ने उसकी अगली तस्वीर सामने रख दी। यही बीते दशक का सबसे बड़ा सामरिक संदेश है।



## मंटीनेशनल कंपनियों में ऐसे करें अप्लाई

बहुत बार लोगों को जब नौकरी की जरूरत होती है, तब उनके पास जॉब स्वीच करने के बहुत कम ऑप्शन होते हैं। इस आर्टिकल में जानें कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जहां आप कभी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

नयी नौकरी ढूँढते वक्त बहुत से लोगों को सही ऑप्शन ना मिलने की समस्या का सामना करना पड़ता है। कंपनियों में निश्चित समय के लिए हायरिंग होती है, जिसके बाद बहुत से उम्मीदवार सही विकल्प की तलाश करने में परेशानी का सामना करते हैं। हालांकि, क्या आपको यह पता है कि कुछ कंपनियों में सालभर जॉब की वैकेंसी निकलती है? आइए जानते हैं इन कंपनियों के बारे में।

भारत में ढेर सारी ऐसा मंटीनेशनल कंपनी हैं, जहां हर वक्त किसी ना किसी पद के लिए हायरिंग हो रही होती है। आपको नौकरी ढूँढने के लिए सबसे पहले मंटीनेशनल कंपनियों की लिस्ट तैयार करनी है। अब इन सभी कंपनियों के जॉब अप्लाई सेक्शन में जाएं और आवेदन दें। किसी भी एमएनएससी में काम करने के लिए अग्रेजी पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दरअसल ज्यादातर एमएनएससी में इंटरव्यू से पहले एक लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है, जिसे क्लियर करना जरूरी होता है।

**टाटा ग्रुप में करें अप्लाई**

टाटा ग्रुप आज भारत का जाना-माना समूह है। टाटा ग्रुप के हाइरिंग पोर्टल पर भी आपको हर वक्त किसी ना किसी पद के लिए हाइरिंग होते हुए मिलगी। हालांकि, जॉब की लोकेशन भारत के अलग-अलग हिस्सों के लिए हो सकती है। टाटा ग्रुप में आवेदन देने के लिए आपको टाटा ग्रुप की वेबसाइट के करियर पेज पर अप्लाई करना है।

**बड़ी कंपनियों को करें टारगेट**

सेमसंग, हिटाची आदि जैसी फेमस कंपनियों में भी पूरे साल हाइरिंग चल रही होती है। पद से जुड़ी सारी जानकारी आपको पार्टल के करियर के सेक्शन में मिल जाएगी। करियर सेक्शन में जाकर आप इन पदों के लिए अपना रिज्यूमे और कवर लेटर भेज सकते हैं।

**पेटीएम**

अगर आप पेटीएम के जॉब सेक्शन में जाएंगे, तो हर वक्त 50 से ज्यादा पदों पर हाइरिंग की जानकारी प्राप्त होगी। आईटी से लेकर एचआर तक से जुड़े पदों पर आवेदन देने के लिए पेटीएम अच्छा ऑप्शन है। अप्लाई करने के लिए 1 टिक बहुत बार हम अपना रिज्यूमे ठीक से नहीं बनाते और बिना कवर लेटर के ही जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। कोशिश करें कि आप कवर लेटर के साथ ही आवेदन करें।



## पशु-पक्षियों की बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण और इलाज से संबंधित है वेटरनरी शाखा

वेटरनरी एक शाखा है, जो पशु-पक्षियों की बीमारियों की स्थिति और चोटों की रोकथाम, नियंत्रण और इलाज से संबंधित है। वेटरनरी कोर्स में पालतू और जंगली जानवरों की बीमारियों और उनके उपचार के बारे में बताया जाता है। पशु कल्याण के बढ़ते महत्व और पशु चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ, ये कोर्स एक आशाजनक और बेहतर करियर का मार्ग प्रदान करते हैं। इसके अलावा, पशु चिकित्सा कोर्स प्रैक्टिकल अनुभव देते हैं। आज के समय में पशु चिकित्सकों की कमी है। इस कोर्स के माध्यम से आप पशु अस्पतालों, चिडियाघरों, प्रयोगशालाओं में नौकरी या अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

**पशु चिकित्सक की पढ़ाई के लिए 12वीं का है महत्व**

इसके लिए छात्रों को 12वीं पीसीबी (भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) के साथ पास करना होगा, ताकि वे पसंदीदा यूनिवर्सिटी और कोर्स में प्रवेश ले सकें। भारत में पशु चिकित्सक बनने के इच्छुक छात्रों को नीट-यूजी या एआईपीवीटी की परीक्षा पास करने की जरूरत होती है। 12वीं के बाद बिना नीट परीक्षा पास किए मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए कई

- विकल्प उपलब्ध हैं
- बीएससी नर्सिंग
  - बीएससी बायोटेक्नोलॉजी
  - बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी
  - बैचलर ऑफ फार्मसी
  - बीएससी मनोविज्ञान
  - बीएससी बायोमेडिकल साइंस
  - बीएससी क्लिनिकल रिसर्च
  - बैचलर ऑफ ऑक्सीपेशनल थेरेपी
  - बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस
  - पशु चिकित्सा विज्ञान

**कोर्स की विविधताएं**

इस क्षेत्र में आपके लिए बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, बीएससी इन वेटरनरी पैथोलॉजी, बीएससी इन एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, बीएससी एनिमल न्यूट्रिशन, बीएससी इन वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी आदि कोर्स मौजूद हैं। आप वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हेल्थ टेक्नोलॉजी, वेटरनरी फार्मसी, एनिमल हसबैंडरी में डिप्लोमा और वेटरनरी मेडिसिन, वेटरनरी सर्जरी में पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप शोध करने के इच्छुक हैं, तो पीएचडी इन वेटरनरी साइंस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। कोर्स के लिए जरूरी ज्ञान अध्ययन के पहले कुछ सालों के दौरान पशु चिकित्सक बनने के लिए जरूरी ज्ञान और सिद्धांतों से परिचित कराया जाएगा। अगले चरण



12वीं के बाद बिना नीट परीक्षा पास किए मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, बीएससी नर्सिंग बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और वेटरनरी कोर्स किए जा सकते हैं।

में उन क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, जिनमें आप सबसे अधिक रुचि रखते हैं। अंत में, आप पशुओं का निरीक्षण और देखभाल करने वाले संगठनों से जुड़ सकते हैं।

**रोजगार के अवसर**

वेटरनरी कोर्स करने के बाद आप पशु सर्जन, चिडियाघर और वन्य जीव पशु चिकित्सा, पशु एनाटॉमिस्ट, वेटरनरी ऑफिसर, पशु रोग विशेषज्ञ, रिसर्वर, पशु चिरौप्रेक्टर, सरकारी और गैर-सरकारी एनिमल हॉस्पिटल से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इनके अलावा, पैरामेडिकल क्षेत्र में भी कई कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें एनर्डीटी की आवश्यकता नहीं होती। इनमें चिकित्सा प्रयोगशाला प्रोद्योगिकी, फिजियोथेरेपी और रेडियोलॉजी जैसे कोर्स शामिल हैं। नीट पास किए बिना मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के कुछ और विकल्प ये हैं, फ्लेबोटोमिस्ट्स (रक्त का नमूना लेने वाले), मेडिकल लेब टेक्नोलॉजिस्ट, पोषण विशेषज्ञ (न्यूट्रिशनिस्ट), फिजिथियन असिस्टेंट। हालांकि, नीट पास किए बिना किए गए इन कोर्सेज में किसी को भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं कहा जाएगा।



## बिना एक्सपीरियंस के भी इन टिप्स की मदद से पा सकते हैं नौकरी

आज के समय में नौकरी पाने के लिए एक्सपीरियंस का होना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इन टिप्स की मदद से नौकरी पा सकते हैं।

जीवन में सफलता पाने की शुरुआत एक्सपीरियंस के साथ होती है। जब आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपको काम का एक्सपीरियंस मिलता है। एक बार एक्सपीरियंस मिल जाने के बाद जॉब रिचक करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन समस्या तब होती है, जब आपके पास काम का एक्सपीरियंस ना हो। अवसर कंपनियां ऐसे लोगों को हायर करने से बचती हैं, जो फेशर हो। दरअसल, फेशर होने के कारण कंपनी सामने वाले व्यक्ति की क्वालिटी का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। ऐसे में फेशर के लिए एक अच्छी जॉब पाना काफी मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि आपने भी अभी-अभी अपनी पढ़ाई खत्म की हो और अब आप एक अच्छी जॉब की तलाश में हों। तो वलिए आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही आसान टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें अपनाकर आप बिना एक्सपीरियंस के भी एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं-

**रिज्यूम को बनाए मजबूत**

किसी भी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए पहले आपको अपना रिज्यूम देना होता है। इसलिए, सबसे पहला और जरूरी कदम है कि आप अपने रिज्यूम को थोड़ा मजबूत बनाने की कोशिश करें। भले ही आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस जॉब के लिए जरूरी रिक्वेल्स को रिज्यूम में मेशन करें। साथ ही, अगर आपने पढ़ाई के दौरान किसी तरह की वर्कशॉप आदि में भाग लिया है तो उसे भी जरूर लिखें। इस तरह छोटी-छोटी खूबियों को हाइलाइट करने से आपको नौकरी मिलने की चांस काफी अधिक बढ़ जाते हैं।

**एंट्री-लेवल जॉब के लिए करें अप्लाई**

चूंकि प्रोफेशनल लाइफ में अभी आपकी शुरुआत है तो ऐसे में आपके लिए एकदम से मनवाही जॉब मिलना काफी कठिन है। शुरुआत में आपको एक्सपीरियंस हासिल करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एंट्री-लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई करें। इस तरह की जॉब्स में कंपनियां पैसा काफी कम देती हैं, लेकिन वे एक फेशर को काम करने का अवसर भी देती हैं। जब आप एंट्री-लेवल जॉब को हासिल कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बेहतर नौकरी पाने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। आप ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से एंट्री-लेवल जॉब ढूँढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं।

**सीखना ना छोड़ें**

अमूमन यह देखने में आता है कि जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो लोग नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बेहतर जॉब की तलाश में हैं तो सीखना कभी भी ना छोड़ें। आप जॉब ढूँढने के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम करते रहें। आजकल ऑनलाइन व ऑफलाइन कई शॉर्ट टर्म कोर्स अवेलेबल हैं। आप अपने फील्ड को ध्यान में रखते हुए अन्य स्किल्स को शॉप करते रहें। इससे आपका रिज्यूम भी बेहतर बनता है और जॉब मिलना भी अधिक आसान होता है।

**नेटवर्क व सोशल मीडिया का सहारा**

नेटवर्किंग व सोशल मीडिया के जरिए भी आपको कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आप कई सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपनी फील्ड के लोगों से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ, अपने काम या स्किल्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट अवश्य करें। इससे लोगों को आपकी क्वालिटी का पता चलता है। इतना ही नहीं, आप अपने दोस्तों, परिवार, प्रोफेसरों और अन्य जानकारों की मदद से प्रोफेशनल कनेक्शन मजबूत करें। अवसर कनेक्शन व नेटवर्किंग की मदद से प्रोफेशनल लाइफ में अपने पैर जमाना काफी आसान हो जाता है।



## अच्छी आवाज के धनी लोगो के लिए डबिंग आर्टिस्ट है अच्छा करियर विकल्प

डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए किसी खास योग्यता की जरूरी नहीं होती है। यदि आप दिलकश आवाज और शानदार भास : के धनी हैं तो आप आसानी से डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं. डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए हाल ही में कुछ कोर्सेज भी शुरू किये गए हैं हैं जिनके लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10 वी पास रहेगी.

योग्यता-

डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आवाज. आपकी आवाज ब्राडकास्टिंग क्वालिटी की होनी चाहिए इससे आप भले ही किसी भी फिल्म या विज्ञापन में अपनी आवाज दे आपकी आवाज आपकी गुणवत्ता को दर्शाएगी. इसके अलावा आपकी भाषा में अच्छी पकड़ भी होनी चाहिए क्योंकि भाषायी कोशल भी इसके लिए बेहद जरूरी है.

आपका सही उच्चारण, आपको अलग अलग तरह से बोल पाने की योग्यता, लोगो के हव भाव को समझ पाने का कोशल भी आपके अंदर होना जरूरी है. आपको डबिंग स्टार के रूप में लोगो के हव भाव को भी समझ कर अपनाना होता है. अच्छे डबिंग स्टार के तोर पर आपको लोगो से कनेक्शन बना पाने की योग्यता भी आनी चाहिए.

अवसर-

डबिंग आर्टिस्ट के तोर पर करियर के कई अवसर उपलब्ध होते हैं. डबिंग स्टार के लिए रेडियो तथा टीवी चैनलो, प्रोडक्शन हाउसेज, विज्ञापन उद्योग, डॉक्यूमेंटरी फिल्मस्, एनिमेशन जगत, ऑनलाइन एजुकेशन (ऑडियो बुक डबिंग) में करियर के अवसर उपलब्ध हैं.. इस क्षेत्र में काफी स्ट्रगल भी है पर एक बार आपका करियर शुरू हो जाता है तो आगे बढ़ने के कई अवसर आपको मिलेंगे.

कोर्स-

इस क्षेत्र में डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स नहीं होते हैं.पर कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाती हैं.जिनकी अवधि एक महीने की होती है.

### संजय सिंह के बयान पर कांग्रेस का तीखा पलटवार



**नई दिल्ली।** विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक से ठीक पहले गठबंधन के अंदरूनी मतभेद और खींचतान एक बार फिर सतह पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन और सीट-शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की टिप्पणी पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने न केवल संजय सिंह के आरोपों को खारिज किया, बल्कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के पूरे रिकॉर्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए। संजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, सबसे पहले, संजय सिंह को इसका जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने अब तक 14 राज्यसभा सांसद भेजे हैं। उन्होंने कितने एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक सांसद भेजे हैं? जो पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं रखती, जो पार्टी झूठ के दम पर सत्ता में आई, क्या वे आज हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

### सपा से राम गोपाल और धनराज ने दाखिल किया नामांकन



**लखनऊ।** राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने दोनों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सपा ने प्रो. रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही प्रत्याशियों ने बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धनराज परिमल नथवानी भारत के एक प्रमुख कॉरपोरेट लीडर और खेल प्रशासक हैं। वह वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज में ररूप प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं और अंबानी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनके पिता परिमल नथवानी भी देश के जाने-माने उद्योगपति और राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने लंदन के रीजेंट बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल बिजनेस में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। उन्हें पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण और फोटोग्राफी का शौक है और वे गुजरात के वन्यजीवों (विशेषकर गिर के शेरों) के संरक्षण से जुड़े अभियानों में भी सक्रिय रहते हैं।

### पीएम मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल की याचिका खारिज



**गांधीनगर।** गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी पद पर बैठा कोई राजनीतिक नेता अपने राजनीतिक हितों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने से जुड़े मामले में उन पर लगाए गए 25,000 रुपये के जुर्माने को चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की डिवीजन बेंच ने कहा अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही में सीआईसी (चीफ इन्क्विजिशन कमीशन) को जिस तरह से जवाब दिया और लिखित बयान दाखिल करके मामले को आगे बढ़ाया, वह अपने आप में सब कुछ बयां करता है और हमें इस पर कोई और टिप्पणी या राय देने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने मार्च 2023 के उस सिंगल जज के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें सीआईसी के 2016 के उस निर्देश को रद्द कर दिया गया था।

### लालू परिवार पर आरोप तय करने कोर्ट में सुनवाई



**नई दिल्ली।** राउज् एवेन्यू कोर्ट, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और कई अन्य लोगों से जुड़े कथित नौकरी के बदले ज़मीन वाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर नए सिरे से दलीलें सुनेगी। अब इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज प्रशांत कुमार करेंगे और आरोप तय करने पर दलीलें 14 और 15 अक्टूबर को सुनी जाएंगी। यह नई सुनवाई इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि इस मामले में आदेश सुरक्षित रखने वाले पूर्व स्पेशल जज विशाल गोगने का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट में हो गया था। दिल्ली हाई कोर्ट की मौजूदा रजिस्ट्रार सूची के अनुसार, डॉ विशाल गोगने 22 सितंबर, 2026 से रजिस्ट्रार के तौर पर कार्यरत हैं। राउज् एवेन्यू कोर्ट में चल रहा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई के ज़मीन के बदले नौकरी वाले केस से जुड़ा है। यह मामला उन आरोपों से संबंधित है जिनमें कहा गया है कि 2004-2009 के दौरान, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे।

### पंजाब कांग्रेस में सियासी ‘सर्जरी’ राजा वड़िंघ की छुट्टी तय



**जालंधर।** पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंघ की जगह नया चेहरा लाने की तैयारी की जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटे में इस पर फैसला हो सकता है। संभावित नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला का नाम सबसे प्रमुखता से सामने आ रहा है। हालांकि अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है और अभी तक पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की यह कवायद पिछले कई महीनों से चल रही अंदरूनी खींचतान की अगली कड़ि मानी जा रही है। राजा वड़िंघ और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच संगठन और नेतृत्व को लेकर मतभेद लगातार चर्चा में रहे हैं। जुलाई में कांग्रेस हाईकमान ने वड़िंघ को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बनाए रखने का फैसला किया था, लेकिन इस फैसले के बाद पार्टी के भीतर विरोध के स्वर और तेज हो गए। चन्नी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की ओर से संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की जरूरत बताई जाती रही।

### भाजपा ने भगवान शिव-राम वाले बयान पर साधा निशाना

## कांग्रेस हिंदू समाज को बांटना चाहती है : सुधांशु त्रिवेदी

**नई दिल्ली।** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस शासित तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के राम अमीरों और शिव गरीबों के भगवान वाले बयान पर आपत्ति जताई है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नास्तिक बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पूरी ताकत से हिंदू समाज को विभाजित करने के हर षड्यंत्र में शामिल है।

भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नास्तिक राहुल गांधी ने 2014 के चुनाव में ईश्वर के नाम पर शपथ ली थी, लेकिन 2024 में उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ नहीं ली। उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली थी। त्रिवेदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का जिक्र करते हुए कहा कि जुबली हिल्स उपचुनाव के संदर्भ में वह पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस पूरी ताकत से हिंदू समाज को विभाजित करने के हर षड्यंत्र में शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू समाज को उत्तर और दक्षिण के नाम पर बांटना चाहती है।

भाजपा प्रवक्ता ने कुछ कांग्रेस नेताओं के पुराने बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक के वित्त मंत्री डीके सुरेश ने कहा था कि दक्षिण ज्यादा टैक्स देता है, जबकि उत्तर कम टैक्स देता है। उन्होंने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के कथित बयान का भी उल्लेख किया और कहा कि वह यह कह चुके हैं कि अगर उत्तर भारत नहीं होता तो दक्षिण कहीं ज्यादा प्रगति करता।

त्रिवेदी ने रेवंत रेड्डी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वह खुद कहते हैं कि हम द्रविड़ियन हैं और वो आर्यन हैं। उन्होंने इस विचार को मूर्खतापूर्ण और निराधार सिद्धांत बताया और दावा किया कि इसे दुनिया भर में नकारा जा चुका है।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि रेवंत रेड्डी को अपने



ही नेताओं के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने उन्हें कांग्रेस के नेता संपूर्णानंद और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को पढ़ने की सलाह दी। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रांतों को विभाजित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने बिहार और तेलंगाना के डीएनए को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस भाषा और फिर जाति के आधार पर भी समाज को विभाजित करना चाहती है।

सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के स्मैश पेट्रीआर्की बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिला और पुरुष के बीच भी विभाजन पैदा करना चाहती है। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेता स्मैश पेट्रीआर्की की बात करते हैं, लेकिन जब केरल के गैंग मुपत्ती की ओर से महिलाओं को लेकर कथित तौर पर टिप्पणी की जाती है तो इन नेताओं की प्रतिक्रिया सामने नहीं आती।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब कांग्रेस भगवानों को भी विभाजित करने की सीमा तक पहुंच गई है। उन्होंने इसे भारत की राजनीति के सबसे निष्कृष्टम उदाहरणों में से एक बताया। अंत में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अंग्रेजों ने देश को बांटा, लेकिन कांग्रेस ने भी सत्ता के उद्देश्य से देश के अलग-अलग हिस्सों और समाज को बांटने का काम किया।

### स्टोल प्रमुख समाचार

### एशियन गेम्स में भारतीय तीरंदाजों ने जीता ट्रिपल गोल्ड

**आइवी नागोया।** भारतीय तीरंदाजों ने एशियन



गेम्स में बुधवार की सुबह भारत को शानदार तोहफा दिया।

कंपांडंड तीरंदाजी के तीनों इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। पुरुष टीम ने फाइनल में चीन को 238-237 से हराकर दिन का तीसरा तीरंदाजी गोल्ड अपने नाम किया। इससे पहले महिला टीम और मिश्रित टीम भी स्वर्ण जीत चुकी थीं।

भारत के तीनों खिलाड़ी युवा हैं। 21 वर्षीय कुशल दलाल, 25 वर्षीय साहिल राजेश और 20 वर्षीय मणि रबम गणेश थिरुमरु की तिकड़ी ने दबाव में धैर्य बनाए रखा और भारत को गोल्ड दिलाया।

साहिल राजेश, कुशल दलाल और मणि रबम गणेश की भारतीय तिकड़ी ने चीन के खिलाफ फाइनल में शानदार जुझारूपन दिखाया। तीन राउंड यानी 18 शॉट के बाद भारत एक अंक से पीछे चल रहा था। तब चीन का स्कोर 179 और भारत का 178 था। इसके बाद आखिरी राउंड में भारतीय टीम ने मुकाबला पलट दिया।

आखिरी छह शॉट में चीन के एक तीरंदाज ने आठ अंक का निशाना लगाया। इसका फायदा भारत को मिला और भारतीय टीम एक अंक की बढ़त पर पहुंच गई। अंत में भारत ने 238 अंक बनाए, जबकि चीन 237 अंक ही हासिल कर सका। इस तरह भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।

भारत ने आज कंपांडंड तीरंदाजी के तीनों इवेंट में स्वर्ण जीता। सबसे पहले चिकित्था तानिपथी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा त्रेत्राम की महिला कंपांडंड टीम ने चीन को हराकर गोल्ड अपने नाम किया था। इसके बाद चिकित्था और साहिल जाधव की मिश्रित टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर भारत की दूसरा स्वर्ण दिलाया। पुरुष टीम ने भी चीन के खिलाफ फाइनल में जीत दर्ज कर तीरंदाजी में भारत का गोल्डन हैट्रिक पूरा कर दिया।

### सैंसेक्स 48 अंक और निफ्टी 95 अंक गिरकर बंद

**मुंबई।** वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में मंदी देखी गई। हालांकि, एक तरफ जहां शेयर बाजार दबाव में रहा, वहीं विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे की मजबूती के साथ 95.81 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 48.78 अंक गिरकर 72,480.29 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 95.75 अंक फिसलकर 22,620.45 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में मंदी के बावजूद चुनिंदा सेक्टरों में स्टॉक-विशिष्ट खेदोदारी देखने को मिली। आज के सत्र में टीसीएस प्रमुख रूप से लाभ में रहा। इसके अलावा मिडकैप इंडेक्स में आरवीएनएल और प्रेस्टीज एस्टेट्स के शेयरों ने शानदार तेजी दिखाई।

### एक महीने में दालों के कीमत 11 प्रतिशत तक बढ़े

**नई दिल्ली।** सरकार की ओर से खाद्य तेल और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बीच दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले महीने में चना, मूंग, मटर और अरहर जैसी मुख्य दालों की थोक कीमतों में 10% तक की तेजी आई है। वहीं, पिछले एक सप्ताह में इनकी कीमतें करीब 3-5% बढ़ी हैं। इंडस्ट्री बॉडी इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने चने की दाल दिल्ली को छोड़कर अन्य प्रमुख बाजारों में करीब 11% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि हफ्ते-दर-हफ्ते इसमें 5.5% की बढ़ोतरी हुई है। अरहर की कीमत में एक महीने में 6.5% और पिछले एक सप्ताह में 2.4% की वृद्धि दर्ज की गई। मूंग के दाम महीनेभर में 10.6% और सप्ताहभर में 4.3% बढ़े। मटर की कीमत भी एक महीने में 6% बढ़ी है।

### आरबीआई रेपो रेट में कट सकता है बढ़ोतरी

**नई दिल्ली।** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आने वाले महीनों में ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी कर सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की नई रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई 2027 की पहली छमाही तक रेपो रेट में कुल 100 बेसिस पॉइंट यानी 1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकता है। ब्रोकरेज ने अपनी पिछली भविष्यवाणी में पहली बढ़ोतरी का अनुमान दिसंबर से आगे बढ़ाकर अक्टूबर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 7 अक्टूबर की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके बाद 75 बेसिस पॉइंट की ओर बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह रेपो रेट 6.25% तक पहुंचने का अनुमान है। बैंक ऑफ अमेरिका ने पहले आरबीआई की ओर से कुल 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। अब ब्रोकरेज ने इसे दोगुना कर 100 बेसिस पॉइंट कर दिया है। हालांकि, यह एक ब्रोकरेज का अनुमान है।

### एफडी में निवेश को लेकर आज से होगा बड़ा बदलाव

**नई दिल्ली।** भारतीय रिजर्व बैंक 1 अक्टूबर 2026 से बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) को लेकर नया नियम लागू करने जा रहा है। इसके तहत बैंकों को बड़ी रकम वाली एफडी पर लागू ब्याज दरों को जानकारी हर कार्यदिवस अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरों में पारदर्शिता बढ़ाना और बड़े निवेशकों को अलग-अलग बैंकों की दरों की तुलना करने में आसानी देना है। नए फ्रेमवर्क के तहत बैंकों को बल्क डिपॉजिट पर लागू ब्याज दरों की जानकारी हर कार्यदिवस सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होगी। अगर बैंक को उस दिन घोषित दरों में कोई बदलाव करना है, तो इसके लिए सुबह 10 बजे के बाद सीमित समय का प्रावधान होगा।

## अंतरिक्ष क्षेत्र में कामयाबी अन्य उद्योगों को सबक

धरती पर या अंतरिक्ष में, का दोहन कर लेगी। विश्लेषकों का मानना है कि 2031 तक, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) से होने वाला राजस्व 440 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो स्पेसएक्स के राजस्व का लगभग 67 फीसदी और परिचालन लाभ का 70 फीसदी होगा।

विश्लेषकों का अनुमान है कि स्पेसएक्स 2031 में अकेले 20 गीगावॉट की अतिरिक्त क्षम्य डेटा सेंटर क्षमता स्थापित करेगा और 2030 के बाद सभी स्थलीय डेटा सेंटरों का विस्तार बंद कर देगा। संदर्भ के लिए, भारत में 2031 तक 10 गीगावॉट की परिचालन डेटा सेंटर क्षमता होने की उम्मीद है।

विश्लेषकों का अनुमान है कि 2031 में स्पेसएक्स के 3,500 से 4,000 स्टारशिप का प्रक्षेपण किया जाएगा। कंपनी की 2031 तक प्रति वर्ष 1,50,000 से अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने



स्टारलैंक ब्रॉडबैंड नेटवर्क को आज के 11,000 उपग्रहों से बढ़ाकर 1,00,000 उपग्रहों तक पहुंचाने और कक्षीय डेटा सेंटर नेटवर्क स्थापित करने के लिए है, जिस पर अंततः कंपनी का खरबों डॉलर का मूल्यांकन टिका हुआ है।

स्टारलैंक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सेवा की बात करें तो विश्लेषक इसे सीधे डिवाइस पर मोबाइल सेवा प्रदान करने में सफल होने का बहुत श्रेय नहीं देते हैं, लेकिन कंपनी 15 करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहकों के साथ उपभोक्ता और उद्यम ब्रॉडबैंड राजस्व में 140

के लिए यह प्रक्षेपण गति आवश्यक है (प्रत्येक स्टारशिप 35 से 50 उपग्रहों को ले जा सकता है)। इन उपग्रहों की आवश्यकता

अरब डॉलर से अधिक की कमाई कर रही है।

इस पूरी योजना का मूल उद्देश्य स्टारशिप रॉकेट का तेजी से और पूर्ण पुनः उपयोग सुनिश्चित करना और प्रति किलोग्राम प्रक्षेपण लागत को 100 डॉलर से नीचे लाना है। कंपनी ने पिछले वर्ष 165 फाल्कन 9 रॉकेट प्रक्षेपित किए, जो आंशिक रूप से पुनः उपयोग योग्य हैं। स्टारशिप अभी भी परीक्षण के अधीन है और इसके त्वरित और पूर्ण पुनः उपयोग की क्षमता का प्रदर्शन करना अभी बाकी है। त्वरित और पूरी तरह पुनः उपयोग के बिना, ऑर्बिटल डेटा सेंटर योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए आवश्यक प्रक्षेपण गति और लागत को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए, पूरी कंपनी स्टारशिप रॉकेट की सफलता पर टिकी है।

विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी 2031 तक 650 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व और 335 अरब डॉलर से अधिक का

परिचालन लाभ अर्जित करेगी। कंपनी स्वयं 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर के राजस्व का अनुमान लगा रही है (जो भारत के वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद का 25 फीसदी है)। इन मॉडलों के अनुसार, कंपनी 2031 तक कोई मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करेगी, जबकि 2026 से 2031 तक इसका पूंजीगत व्यय 1.76 लाख करोड़ डॉलर से अधिक होगा। भारत में निफ्टी 500 में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल वार्षिक पूंजीगत व्यय लगभग 100 अरब डॉलर है। स्पेसएक्स का अध्ययन करने से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के महत्व का कुछ अंदाजा लगता है। चाहे आज संचार या निगरानी हो या भविष्य में डेटा सेंटर, युद्ध और अंतरिक्ष आधारित विनिर्माण, अंतरिक्ष भविष्य के विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। अंतरिक्ष में प्रक्षेपण क्षमता और उपग्रह डिजाइन एवं निर्माण दक्षता दोनों ही महत्वपूर्ण होंगी।

मुख्यमंत्री साय देवेंद्र नगर चौक से लाल चौक तक नशामुक्ति पदयात्रा में हुए शामिल

# नशामुक्त और स्वस्थ छत्तीसगढ़ से ही बनेगा विकसित छत्तीसगढ़ : विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर में देवेंद्र नगर चौक से लाल चौक तक आयोजित नशामुक्ति पदयात्रा में शामिल हुए। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राओं, युवाओं, महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री श्री साय ने पदयात्रा कर नशामुक्त और स्वस्थ समाज के निर्माण का संदेश दिया। पदयात्रा के समापन पर मुख्यमंत्री श्री साय ने लाल चौक स्थित लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नशामुक्त और स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बनेगा। नशा केवल किसी एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसका दुष्प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। विशेष रूप से युवाओं को नशे से बचना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वयं नशे से दूर रहने और अपने आसपास के लोगों को भी नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करने की अपील की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवा किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। युवा स्वस्थ होंगे, शिक्षित और कुशल होंगे तथा अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाएंगे तो प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार युवाओं के लिए शिक्षा,



कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, खेल और उद्यमिता के अवसरों का विस्तार कर रही है। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ का प्रत्येक युवा अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग अपने परिवार, समाज और प्रदेश की प्रगति में करे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितम्बर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक नशामुक्ति पदयात्रा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने संयम, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया था। ऐसे में नशामुक्ति का यह अभियान उनके विचारों

को जन-जन तक पहुंचाने का भी सशक्त माध्यम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में सेवा को सर्वोपरि रखा है। 17 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रारंभ हुई उनकी शासन की यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विभिन्न जनसेवा गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अभियान के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता और जनसेवा के विभिन्न कार्यों में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

## हजारों लोगों ने नशामुक्ति का संकल्प लिया

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि इन पदयात्राओं से प्रेरित होकर अब तक हजारों लोगों ने नशामुक्ति का संकल्प लिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नशामुक्ति पदयात्रा सप्ताह भी अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनेगा और विशेष रूप से युवाओं को स्वस्थ एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने उपस्थित छात्र-छात्राओं और युवाओं से आह्वान किया कि वे नशामुक्ति के संदेश को अपने परिवार, मित्रों और समाज तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ युवा, एक स्वस्थ परिवार और एक जागरूक समाज मिलकर ही स्वस्थ, सशक्त और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास, फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष श्रीमती मोना सेन, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता साहू सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, छात्र-छात्राएं, युवा, महिलाएं एवं आमजन उपस्थित थे।

## कृषि में नवाचार की असीमित संभावनाएं : रामविचार नेताम



### कृषि विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेनोरशिप कॉन्क्लेव का समापन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में नवाचार एवं स्टार्टअप स्थापित करने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवाओं की है जिनके मन में कुछ नया करने का जूनून है। इन युवाओं को कृषि के क्षेत्र में उपलब्ध असीमित संभावनाओं को तलाश कर अपने नवाचारी विचारों के साथ स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए और एक नई सोच के साथ देश के विकास को नई गति प्रदान करना चाहिए। श्री नेताम ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार स्टार्टअप इंडिया

एवं स्किल इंडिया जैसी अभिनव योजनाओं के माध्यम से नवाचार एवं स्टार्टअप को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी निपुण जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्टार्टअप एवं लघु मध्यम उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित कर रही है। कृषि मंत्री श्री नेताम आज यहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि मंडप में 28 से 30 सितम्बर तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से आयोजित छत्तीसगढ़ यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेनोरशिप कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

## डेटा लेबलिंग और एआई में बलरामपुर ने रचा इतिहास

रायपुर। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर-रामानुजगंज जिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा लेबलिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहाँ कॉर्गिन्टिव डेटा एनोटेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले के शिक्षित ग्रामीण युवाओं और स्व-सहायता समूह की महिलाओं को एआई आधारित अत्याधुनिक रोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है।



कलेक्ट्रेट कक्ष में जिला प्रशासन बलरामपुर-रामानुजगंज और प्रिन्मा एआई के बीच इस सेंटर की स्थापना के लिए एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (स्म) पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ

श्री आशुतोष चतुर्वेदी, प्रिन्मा एआई के सीईओ डॉ. श्रीराम अय्यर, सीओओ श्री अमिताभ राय चौधरी, सीटीओ श्री विनीत कुमार झा तथा स्व-

सहायता समूह की सदस्य सुश्री सपना व सुश्री अनुजा प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। पायलट चरण के तहत बलरामपुर में 10 सीटों का सेंटर शुरू होगा, जिसमें एक समर्पित प्रशिक्षक और गुणवत्ता पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे।

## मुख्यमंत्री विष्णुदेव के मार्गदर्शन में आंगन मिलन सम्मेलन का आयोजन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रायपुर जिले में आंगन मिलन सम्मेलन का आयोजन किया गया।

सम्मेलन के अंतर्गत जिले के 207 आंगनवाड़ी केंद्रों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, माताओं, बच्चों तथा स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती माताओं की गोदभराई एवं बच्चों



का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। इस अवसर पर माताओं एवं परिवारजनों को गर्भावस्था के दौरान आवश्यक देखभाल, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, बच्चों के उचित पोषण, स्वास्थ्य तथा प्रारंभिक बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

## मुख्यमंत्री साय की पहल पर राज्योत्सव में दिखेगा वायुसेना का शौर्य

रायपुर। मुख्यमंत्री वष्णु देव साय की पहल पर राज्योत्सव को इस बार और भी यादगार बनाने की तैयारी की जा रही है। राज्योत्सव छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विकास और उपलब्धियों के उत्सव के साथ प्रदेशवासियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव भी बने, इसी कड़ी में 2 नवंबर 2026 को नवा रायपुर के आसमान में भारतीय वायुसेना के शौर्य, साहस और अद्भुत कौशल का रोमांचकारी प्रदर्शन देखने को मिलेगा।

भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध



‘सारां’ हेलीकॉप्टर डिस्ले टीम छह हेलीकॉप्टरों के साथ रोमांचकारी एयरोबेटिक शो प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही वायुसेना के तीन अन्य हेलीकॉप्टर

भी कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध ‘आकाशगंगा’ पैराशूट डिस्प्ले टीम के सदस्य आसमान से पैराशूट जंप कर हैटअंगेज करतब दिखाएंगे। इस भव्य आयोजन में भारतीय वायुसेना के 100 से अधिक अधिकारी एवं जवान शामिल होंगे।

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज भारतीय वायुसेना एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक की।

## छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

### आयुष्मान के आलावा मरीजों से नगदी वसूला जा रहा : कांग्रेस

रायपुर। निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत कार्ड के बावजूद सता के संरक्षण में मरीजों से अवैध वसूली और रसीद अतिरिक्त पैसे देने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला है कि सरकार को अकर्मण्यता से आज छत्तीसगढ़ का गरीब और मध्यमवर्गी स्वास्थ्य आपातकाल से गुजर रहा है। भाजपा की साय सरकार में ‘आयुष्मान कार्ड’ इलाज का जरिया नहीं बल्कि सता के चहेते चंद निजी अस्पतालों के लिए उगाही का लाइसेंस बन चुका है। मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, कार्ड जमा करता है फिर भी उससे बिना बिल दिए 20 से 50 हजार रुपये नकद ऐंटे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का संरक्षण प्राप्त निजी अस्पताल छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूट रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी गहरी नींद सोए हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार मुफ्त इलाज का ढोल पीटती है, लेकिन जमीनी यह है कि कार्ड दिखाने के बाद भी निजी अस्पताल कैश मांग रहे हैं। बिल मांगने पर इलाज रोकने या डिस्चार्ज करने की धमकी दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग और नोडल एजेंसी का निजी अस्पतालों पर से नियंत्रण खत्म हो चुका है। ऑडिट और औचक निरीक्षण की प्रक्रिया ठप है।



### सरकार के कुप्रबंधन से राशन दुकानें बढहाल : कांग्रेस

रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पूरी तरह ध्वस्त करने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार की दुर्भावना से हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है, पीडीएस दुकानों में सर्वर और ई-पास मशीनों की खराबी का बहाना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से गरीबों के अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। हाल ही में राशन एटीएम का बड़े धूम-धाम से उद्घाटन किया गया, लेकिन दो महीने के भीतर ही ज्यादातर जगहों पर मशीनें बंद हो गई हैं, जहां चालू है वहां पर भी कई जगह प्रति हितग्राही आधे से एक किलो चावल कम निकल रहा है। राशन एटीएम योजना पूरी तरह से छलावा साबित हुआ है। शक्कर, गुड़, चना और नमक जैसी मूलभूत वस्तुएं पीडीएस राशन दुकानों से नदारद है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार की अकर्मण्यता के चलते छत्तीसगढ़ की राशन दुकानें इस समय भारी अव्यवस्था का शिकार हो चुकी हैं, जिसके चलते लाखों गरीब हितग्राही अपने जायज राशन से वंचित हो रहे हैं, उनका राशन लैप्स हो रहा है।



### स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित



रायपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्द्वारा राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान , रायपुर में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत संस्थान में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व को रेखांकित करना था। शिविर के दौरान संस्थान के सभी सफाई कर्मियों की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की गई। इसमें रक्तचाप एवं रक्त शर्करा की जांच के साथ-साथ उनके सामान्य स्वास्थ्य, पूर्व से चली आ रही बीमारियों तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परामर्श प्रदान करते हुए उन्हें रोगों की समय पर पहचान, नियमित जांच, संतुलित आहार एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक किया गया। स्वस्थ जीवन के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय-समय पर स्वास्थ्य की जांच से संभावित रोगों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान की जा सकती है।

### गिरधौना में आंगन मिलन उत्सव का आयोजन



बिलासपुर। सेवा संकल्प अभियान के सेक्टर गिरधौना के आंगनवाड़ी केंद्र खैरी क्रमांक-2 में आंगन मिलन उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष श्रीमती माधवी वस्त्रकार, जनपद सदस्य रामकुमार सिंगरौल, सरपंच श्रीमती राजकुमारी सोनवानी, पंच प्रेमलाल सिंगरौल सहित रोहित, नीलसरोज सिंगरौल, लक्ष्मण धुवे एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती कमलेश कौशिक, आंगनवाड़ी सहायिका श्रीमती दीपा मेहर एवं मितानिन श्रीमती शैली मेहर को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं महतारी वंदन योजना की हितग्राही श्रीमती किरण मानिकपुरी को योजना से प्राप्त राशि का उपयोग पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में करने के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हितग्राही श्रीमती सुखमनी मरकाम को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।

### सेवा संकल्प अभियान में जल संरक्षण और जनभागीदारी का संदेश

बिलासपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा विकासखंड कोटा के ग्राम खनपुर में ‘जल संरक्षण एवं जनभागीदारी’ पर केन्द्रित ‘जल जन सेवा संकल्प’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं पंचायत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, महिलाओं एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्री मोहित जायसवाल सहित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति रही। जल संसाधन संभाग कोटा के अनुविभागीय अधिकारी अखिलेश कुमार राठौर ने जल संरक्षण, जनभागीदारी तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। पीएचई विभाग के उप अभियंता द्वारा जल जीवन मिशन सहित पेयजल से जुड़ी योजनाओं एवं जल के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि श्री मोहित जायसवाल ने कहा कि जल का संरक्षण केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। वर्तमान में जल की बचत आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की बुनियाद है। उन्होंने ग्रामीणों से वर्षा जल के संचयन और पानी के सदुपयोग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया कार्यक्रम में संचाई से वंचित क्षेत्रों को संचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

## 11 युवाओं को मोके पर मिले ऑफर लेटर संभाग स्तरीय रोजगार मेले में 388 युवाओं का चयन

बिलासपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रोजगार विभाग बिलासपुर द्वारा आज मॉडल आईटीआई कोनी में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न सेक्टरों से जुड़ी 18 कंपनियों ने लगभग 1765 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं ने मेले में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न पदों के लिए 6624 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2970 आवेदक साक्षात्कार में शामिल हुए। कंपनियों द्वारा 765 आवेदकों को प्रारंभिक रूप से चयनित किया गया तथा 388 युवाओं का अंतिम चयन किया



गया डू रोजगार मेले में कमिश्नर सुनील कुमार जैन, कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं अपर कलेक्टर सुश्री डॉ. ज्योति पटेल उपस्थित रहीं। अधिकारियों ने विभिन्न कंपनियों के स्टॉलों का अवलोकन किया और नौकरी के लिए पहुंचे युवाओं से चर्चा कर उनका उत्साहवर्धन किया।

कमिश्नर श्री जैन ने कहा कि रोजगार मेले युवाओं और नियोक्ताओं के बीच एक उपयोगी सेतु का काम करते हैं। एक ही स्थान पर विभिन्न कंपनियों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलने के साथ युवाओं को अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी पाने का अवसर मिलता

है। उन्होंने चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए अन्य युवाओं से भी अपने कौशल को लगातार निखारने का आह्वान किया।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि जिले के युवाओं को स्थानीय एवं प्रतिष्ठित निजी संस्थानों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिलासपुर में नियमित रूप से रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को अलग-अलग कंपनियों के चक्र लगाने के बजाय एक ही मंच पर अनेक रोजगार विकल्प उपलब्ध होते हैं। जिला प्रशासन का प्रयास

### सरकार की लापरवाही से धान सड़ रहा, शार्टज हो रहा : कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में धान खरीदी के साथ-साथ उठाव और कस्टम मिलिंग का समयबद्ध चक्र चलता था, मिलर्स के लिए 72 घंटे के भीतर उठाव का नियम था, मिलिंग करके 67 प्रतिशत चावल तय समय के भीतर शासन में जमा करने का नियम था, एक-एक दाना सुरक्षित गोदामों तक पहुंचता था, जिसकी अवहेलना भ्रष्टाचार की नियत से भाजपा की सरकार कर रही है। सरकार और उनके चहेते चंद मिलरों की साठगांठ के कारण धान सड़ने का नाटक रचा जा रहा है, ताकि बाद में इसे रद्दी बताकर कौड़ियों के दाम बेचा जा सके या घपलेबाजी पर पदा डाला जा सके।

## वोट चोरी देश के साथ गद्दारी पीएम मोदी इस्तीफा दे : दीपक बैज

रायपुर। वोट चोरी देश के साथ गद्दारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर देश की चुनाव प्रणाली को दूषित करने का काम किया है। एसआईआर के नाम पर भाजपा के इशारे पर देश के 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गये हैं। यह देश के लोकतंत्र के साथ गद्दारी है। ज्ञानेश कुमार ने यह कृत्य मोदी के सत्ता को बनाये रखने के लिये भाजपा को चुनाव जिताने के लिये किया है। इसलिये प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से इस्तीफा दे तथा ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से बर्खास्त किया जाये।



दीपक बैज ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में एसआईआर में मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने में 14 मौकों पर लिखित आपत्तियां व्यक्त किया तथा टिप्पणियां किया लेकिन उनको नजरअंदाज कर

दिया गया। यह सारे तथ्य आयोग के रिकार्ड में हैं जबकि आयोग का काम बहुमत के आधार पर चलता है ऐसे में दो आयुक्तों की आपत्तियां दरकिनार किया जाना, बहाली की जाये। प्रदेश एसआईआर के काम में मनमानी कर देश के 13 करोड़ मतदाताओं का नाम कटवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर काम करने वाली कठपुतली की भूमिका निभाई है और गृह मंत्री खुद प्रधानमंत्री की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नियुक्त हैं।